



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 2018/चैत्र 30, 1940

No. 140]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 2018/CHAITRA 30, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटन-रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2018

अंतिम जांच परिणाम

**विषय:** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विस्कोस फिलामेंट यार्न" के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क की जांच।

**फा. सं. 15/16/2016-डीजीएडी:**—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटन-रोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए

1. यतः उपरोक्त अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 7 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या 14/23/2004-डीजीएडी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित निर्यातित "विस्कोस फिलामेंट यार्न" (जिन्हें आगे "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच शुरू की थी। प्राधिकारी ने 4 अप्रैल, 2006 को अधिसूचित किए गए जांच परिणाम में चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित निर्यातित "विस्कोस फिलामेंट यार्न" के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 24 मई, 2006 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 45/2006 द्वारा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक और पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे।

2. लगाए गए शुल्क की समय-समय पर समीक्षा की गई है और प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22 मई, 2009 को अधिसूचना संख्या 15/8/2007-डीजीएडी द्वारा मध्यावधि समीक्षा के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किया गया था जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "संबद्ध वस्तुओं" पर पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लागू रखे जाने की सिफारिश की गई थी। प्राधिकारी की सिफारिशों के

अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 81/2009-सीमा-शुल्क द्वारा पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे।

3. पाटन-रोधी शुल्क को जारी रखे जाने में परिवर्तन करने के याचिकादाता के अनुरोध पर निर्णायक समीक्षा जांच करने के बाद प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे जिसमें दिनांक 24 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/23/2010-डीजीएडी द्वारा पाटन-रोधी शुल्क के रूप में परिवर्तन करने की सिफारिश की गई थी। दिनांक 4 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 23/2012-सीमा-शुल्क के अनुसार पाटन-रोधी शुल्क लागू किए गए थे।

4. यतः अधिनियम और नियमावली के अनुसार जब तक पाटन-रोधी शुल्क को पहले रद्द नहीं कर दिया जाता है, तब तक वे उन्हें लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले निष्प्रभावी नहीं होंगे।

5. और उपरोक्त स्थिति होने के बावजूद प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत् पर्याप्त प्रमाणों से युक्त अनुरोध के आधार पर उपायों के समाप्त होने की तारीख से पूर्व उचित समय के भीतर इसकी जांच करने की आवश्यकता होती है कि क्या शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

6. और यतः मेसर्स केसोराम रेयन जो कि मेसर्स किंगनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक यूनिट है और मेसर्स इंडियन रेयन जो कि मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक यूनिट है (जिन्हें आगे याचिकादाता अथवा आवेदक भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष वर्तमान मामले में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “विस्कोस फिलेमेंट यार्न” (जिन्हें आगे “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “संबद्ध वस्तुओं” के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्कों की मौजूदा मात्रा को बढ़ाने का अनुरोध किया था।

7. और यतः प्राधिकारी ने याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर दिनांक 24 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या 10/2017-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी कि क्या के संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू उक्त शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 3 मई, 2017 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 14/2017 द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटन-रोधी शुल्कों की वैधता अवधि को दिनांक 3 मई, 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

8. वर्तमान समीक्षा के दायरे में चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित मूल्य जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

### **ख. क्रिया-विधि**

9. प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त जांच शुरू करने के लिए अधिसूचित सार्वजनिक सूचना को जारी करने के बाद इस जांच के संबंध में में निम्नोक्त क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

- (i) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले पाटन-रोधी आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास/प्रतिनिधि को अधिसूचित कर दिया था।
- (ii) प्राधिकारी ने जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ याचिकादाता द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को भी प्रेषित की गई थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे जांच शुरू करने की अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्राधिकारी को लिखित रूप से अपने विचारों से अवगत करा दें।
- (iii) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन-पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की एक प्रति प्रदान की थी।
- (iv) भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे अपने देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत कर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों की प्रति के साथ संबद्ध देश के दूतावास भी भेजी गई थी।
- (v) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

(क) जिबिन ग्रास कंपनी लिमिटेड

- (ख) जिलिन केमिकल फाईबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- (ग) जिलिन एन्का विस्कोस कंपनी लिमिटेड
- (घ) जिविन हीस्ट फाईबर कंपनी लिमिटेड
- (ङ) हेंगझाऊ बी. पी. केमिकल फाईबर कंपनी
- (च) बोर्डिंग स्वान ग्रुप
- (छ) किसनकिसआंग बल्लु केमिकल फाईबर
- (vi) उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में कुछ निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं/निवेदन किए हैं। निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :-
- (क) जिलिन केमिकल फाईबर स्टॉक कंपनी लिमिटेड
- (ख) जिलिन एन्का विस्कोस कंपनी लिमिटेड
- (ग) जिविन हीस्ट फाईबर कंपनी लिमिटेड
- (घ) किसनकिसआंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड
- (vii) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित जात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-
- (क) शाह ट्रेडिंग कंपनी
- (ख) व्यापार कॉम एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (ग) यश इंटरप्राइजिज
- (घ) डोरीवाला इंडस्ट्रीज
- (ङ) मारवाड़ी ब्रदर्स
- (च) राजमल सन्स एंड ग्रुप
- (छ) चुन्नीलाल कुन्दनमल
- (ज) शान्ति टेक्सटाईल्स
- (झ) कृष्ण सेल्स कॉर्पोरेशन
- (ञ) बिट्टू सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
- (ट) अमृत रेयन
- (viii) संबद्ध वस्तुओं के उपरोक्त आयातकों में से किसी ने भी इस मामले में प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, संबद्ध वस्तुओं के दो आयातकों नामतः मेसर्स रीघन फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड और मेसर्स लिबर्टी ट्रेन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड ने जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना का उत्तर दिया है और प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।
- (ix) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त एक सार्वजनिक फाईल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच करने के लिए खुले उपलब्ध कराए हैं।
- (x) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वह जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने की व्यवस्था करें, जो कि प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा का परिकलन और आवश्यक विश्लेषण करने के लिए, कारोबार की विधिवत् जांच करने के बाद डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है तथा इस अंतिम जांच परिणाम में विश्वास किया है।
- (xi) भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और उनको निर्मित करने और बेचने के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और आकलन किया गया है, ताकि क्षति मार्जिन का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत का निर्धारण, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।

- (xii) नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करने के लिए 16 मार्च, 2018 को एक मौखिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई के समय जिन सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए गए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।
- (xiii) जितना आवश्यक समझा गया था, घरेलू उद्योग के आंकड़ों की स्थल पर जांच की गई थी। इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ जहां कहीं भी लागू होता है, वहां आवश्यक आशोधन सहित ऐसी सत्यापित सूचना पर विश्वास किया गया है।
- (xiv) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक (12 महीने) मानी गई है। क्षति विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रवृत्तियों की जांच में अवधि में अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 और अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016 तथा जांच की अवधि भी शामिल है।
- (xv) इस जांच की कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को जहां कहीं भी प्रासंगिक पाया गया है, प्राधिकारी द्वारा उनका निदान इस प्रकटन विवरण में कर दिया गया है।
- (xvi) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।
- (xvii) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।
- (xviii) 10.04.2018 को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया था, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्य निहित थे और प्रकटन विवरण पर यदि कोई टिप्पणी की जानी है, तो उसे प्रस्तुत करने के लिए 17.04.2018 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन के पश्चात् प्राप्त हुई टिप्पणियों पर प्राधिकारी ने उचित रूप से विचार किया है।
- (xix) इस प्रकटन विवरण में हितबद्ध पक्षकार द्वारा \*\*\* सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर उसी प्रकार से विचार किया गया है।
- (xx) जांच अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 67.95 रुपए है।

## **ख. विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु"**

### **ख. 1 घरेलू उद्योग के विचार**

10. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:-

- (1) वर्तमान समीक्षा जांच एक निष्पक्ष समीक्षा जांच है। मूल जांच और वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद 150 डाईनर्स (और उसमें  $\pm 4\%$  का स्वीकार्य अंतर का) विस्कोस रेयन फिलेमेंट यार्न है। वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल विचाराधीन उत्पाद वही है, जो कि जिस पर मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिया गया है। विस्कोस रेयन फिलेमेंट यार्न एक पुनःसृजित सेल्युलोजी यार्न है। यह ऐसे सिंथेटिक यार्न से भिन्न है जिसे पेट्रोलियम उत्पादों से उत्पादित किया जाता है। विस्कोस रेयन फिलेमेंट यार्न काष्ठ गूदे जैसे प्राकृतिक नवीकरण-योग्य संसाधनों से उत्पादित किया जाता है। यह 100% बायोडिग्रेडेबल और पारिस्थितिकी अनुकूल होता है।
- (2) विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा कि मूल जांच की कार्यवाही में वर्णित किया गया है।
- (3) विगत तीन वर्षों में विस्कोस रेयन फिलेमेंट यार्न के दायरे के संबंध में कुछ भ्रांति रही थी, जिसे जांच के दायरे से बाहर निकाल दिया गया था। तदनुसार, सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने उचित जांच करने के प्रयोजनार्थ संबद्ध वस्तुओं की निष्काषित श्रेणी की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए एक विवरण जारी किया था।
- (4) पाटन-रोधी शुल्क की जांच की शुरुआत करने के पश्चात् पाटन-रोधी शुल्क का अपवंचन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विवरण प्रयुक्त किए गए हैं और नए विवरण अन्वेषित किए गए हैं।

- (5) विस्कोस फिलेमेंट यार्न को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्ष 5403.31, 5403.31, 5403.32, 5403.33 और 5403.41 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- (6) संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन तीन प्रक्रियाओं नामतः कंटीन्युस स्पन यार्न (सीएसवाई), पोर्ट स्पन यार्न (पीएसवाई) और स्पॉट स्पन यार्न (एसएसवाई) से किया जा सकता है। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन इन समस्त तीन प्रक्रियाओं से करता है। तथापि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन, पोर्ट स्पन यार्न (पीएसवाई) और कंटीन्युस स्पन यार्न (सीएसवाई) प्रक्रियाओं से किया जाता है।
- (7) बांस के फाईबर को विचाराधीन उत्पाद के वर्तमान दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वर्तमान जांच, एक निर्णायक समीक्षा जांच है और जांच के इस चरण में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। पक्षकार ने 75 डाइनर्स से कम के विस्कोस फिलेमेंट यार्न को बाहर रखने का भी अनुरोध किया है, लेकिन इसे उपरोक्त कारणों और साथ ही इस कारण से भी बाहर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि पक्षकार 75 डाइनर्स से कम के विस्कोस फिलेमेंट यार्न को बाहर रखने का कोई अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है।
- (8) यह निवेदन किया गया था कि वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने उत्पाद के दायरे में संशोधन नहीं किया है। बल्कि उसने दायर की गई अपबन्धना की याचिका के उत्तर में दिनांक 11 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 15/25/2014-डीजीएडी द्वारा विचाराधीन उत्पाद की बहिष्कृत श्रेणी के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था।
- (9) हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया था कि कशीदाकारी के गैर-रंजित यार्न को ऐसे किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए विचाराधीन उत्पाद प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा आरोप वास्तव में गलत है और उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- (10) अन्य हितबद्ध पक्षकार ने भी वर्तमान जांच में अपनाए गए पीसीएन में असंगतता होने का दावा किया था। तथापि, यह पक्षकार ऐसे पीसीएन की किस्म के बारे में कोई सुझाव देने में विफल रहा है, जिसे अपनाया जा सकता है।
- (11) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जांच की है जिस पर विश्वास किया गया है।

## **ख. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में कशीदाकारी के गैर-रंजित यार्न को उत्पाद के दायरे के भीतर शामिल किया गया है, लेकिन यह वही यार्न है, जिसे मूल जांच के साथ-साथ प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था और इसलिए इसे बाहर रखा जाना चाहिए।
- (2) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 14.07.2016 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 32/2016-सीमा-शुल्क (पाटन-रोधी शुल्क) में मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसे विधि के प्राधिकारी अथवा अधिकार-क्षेत्र के बिना जारी किया गया है। इस अधिसूचना में उत्पाद के दायरे को बढ़ाने और "कशीदाकारी के गैर-रंजित यार्न" को उत्पाद के दायरे के भीतर शामिल करने का कोई उचित कारण प्रकट नहीं किया गया है।
- (3) मूल जांच में संज्ञान में रख कर कशीदाकारी के यार्न को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था और उसको शामिल करने के बाद के अनुरोध को, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मध्यावधि समीक्षा जांच में और साथ ही प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।
- (4) कशीदाकारी के यार्न, विस्कोस फिलेमेंट यार्न के समान वस्तु नहीं है।
- (5) याचिकादाता द्वारा प्रस्तावित पीसीएन के अनुसार विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि विभिन्न प्रोद्योगिकियों से संघटित उत्पाद में कोई विशेष अंतर नहीं है।
- (6) एसएसवाई एक ऐसी प्रोद्योगिकी है, जो कि पीएसवाई से उन्नत है, लेकिन यह सीएसवाई से कम उन्नत है और यह पीएसवाई की प्रोद्योगिकी के समान है। इस प्रकार एसएसवाई द्वारा उत्पादित विस्कोस फिलेमेंट यार्न, पीएसवाई और सीएसवाई द्वारा उत्पादित विस्कोस फिलेमेंट यार्न से भिन्न नहीं है।
- (7) बांस से विनिर्मित विस्कोस फिलेमेंट यार्न को वर्तमान दायरे से बाहर रखने का यह आधार है कि इसमें भिन्न कच्चे माल, भिन्न अनुप्रयोग, भिन्न बाजार की पूर्ति करने के लिए और भिन्न आईडी संख्याओं को प्रयुक्त किया जाता है और साथ ही इसका एक मात्र कारण यह भी है कि दोनों उत्पादों एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं।

- (8) 75 डाईनर्स से कम के विस्कोस फिलेमेंट यार्न को वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखे जाने और विचाराधीन उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- (9) याचिकादाताओं ने पाटन-रोधी शुल्क की अपवचना करने का कोई अधिप्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके फलस्वरूप आयातित उत्पाद का गलत विवरण दिया गया है।
- (10) निर्दिष्ट प्राधिकारी समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुनःजांच अथवा उसका पुनर्निर्धारण नहीं कर सकते हैं।
- (11) प्राधिकारी को ऐसे कशीदाकारी यार्न की किस्मों को स्पष्ट परिभाषित करने की आवश्यकता है, जिन्हें पाटन-रोधी शुल्क के दायरे से निरंतर बाहर रखा जा रहा है।

### ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 150 डाईनर्स (और उसमें  $\pm 4\%$  का स्वीकार्य अंतर का) विस्कोस रेयन फिलेमेंट यार्न है, जिसमें 67 डेसिटेक्स से कम का मोनो फिलेमेंट यार्न शामिल है, जिसे विस्कोस फिलेमेंट यार्न अथवा वीएफवाई, रेयन फिलेमेंट यार्न, कृत्रिम रेशम यार्न, सेल्युलोज यार्न अथवा रेयन यार्न के नाम से भी जाना जाता है और इनमें 100% विस्कोस यार्न से निर्मित रंजित यार्न, फ्लेट यार्न, माईक्रोफिलेमेंट माईक्रो यार्न, ट्विस्टिड यार्न (कशीदाकारी यार्न के बहिष्करण सहित), दोहरे/बहुविध प्लाई के वीएफवाई आदि जैसे सभी यार्न (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) भी तब तक शामिल हैं, जब तक कि उन्हें इस पैरा में विशेष रूप से बाहर नहीं रखा जाता है। इसके अतिरिक्त विचाराधीन उत्पाद में कशीदाकारी यार्न शामिल नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रंजित विस्कोस यार्न कशीदाकारी का धागा, सिलाई का धागा, फर यार्न, फायर रिटारडिड यार्न, इंजीनियर्ड यार्न और एंटी-टेक्चराईज्ड यार्न उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

13. संबद्ध वस्तुओं को सीमा-शुल्क के उप-शीर्ष 54033100, 54033200, 5403300, 54034110, 54034120, 54034130, 54034140, 54034150, 54034160, 54034170, 54034180 और 54034190 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, हालांकि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि इन्हें (इस संबंध में की गई विगत जांच में) अन्य अध्याय के शीर्ष के अंतर्गत आयातित किया गया है। इस प्रकार सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

14. बाद के चरण में याचिकादाताओं ने प्राधिकारी को अपवचना याचिका दायर की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि निर्यातक कशीदाकारी के यार्न के रूप में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए प्राधिकारी ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के बारे में स्पष्ट किया गया था।

15. इसके अतिरिक्त सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 14.09.2016 को अधिसूचना संख्या 32/2016 द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जिसमें कशीदाकारी यार्न के दायरे को परिभाषित किया गया था। विभिन्न पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना की कानूनी वैधता को चुनौती दी गई थी और विश्लेषण के लिए उसे दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया था। अधिसूचना और उस पर दिए गए स्पष्टीकरण की व्यापक जांच करने के बाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि –

“.....क. पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से उत्पाद को बाहर रखने के लिए एक यार्न को कशीदाकारी का यार्न/धागा माना जाता है, जो कि उत्पाद में प्रयुक्त करने के लिए परिष्कृत होता है.....

ख. इसलिए इसका यह तात्पर्य होगा कि परिभाषा से कशीदाकारी का यार्न रंगीन होता है और सफेद रंग भी एक रंग होता है, जो कि कच्चे यार्न के संसाधन के फलस्वरूप होता है.....

ग. अन्य शब्दों में रंग की ओर ध्यान दिए बिना संबंधित उत्पाद, “कशीदाकारी के यार्न” की परिभाषा के भीतर आना चाहिए, जैसा कि दिनांक 14.07.2016 की अधिसूचना द्वारा स्पष्ट किया गया है..... ”

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि “कशीदाकारी के यार्न” को उत्पाद के वर्तमान दायरे से बाहर रखा गया है और उसे वर्तमान जांच शुरू करने की अधिसूचना में विस्तार से उल्लिखित बहिष्कृत मदों की परिभाषा के भीतर सम्मिलित किया गया है।

17. वर्तमान जांच के निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते और जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पहले सिफारिश की गई है, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटन-रोधी शुल्क को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा है, जैसा कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के अनुसार मूल जांच और परवर्ती समीक्षा जांच में था। इसलिए बांस के फाईबर से निर्मित विस्कोस फिलेमेंट यार्न (वीएफवाई) और 75 डाईनर्स से कम के विस्कोस फिलेमेंट यार्न के बहिष्करण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

18. समान वस्तु के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

*“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*

19. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह मानना है कि भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित तथा संबद्ध देश से आयातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद, भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय वस्तुएं हैं। ये दोनों वस्तुएं वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।

20. इस प्रकार प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद समान वस्तु है।

#### **घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसका आधार**

##### **घ.1 घरेलू उद्योग के विचार**

21. घरेलू उद्योग के दायरे और उसके आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) मेसर्स केसोराम रेयन, जो कि मेसर्स किंगनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक यूनिट है और मेसर्स इंडियन रेयन, जो कि मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक यूनिट है द्वारा विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक होने के नाते याचिका दायर की गई है और इसका समर्थन मेसर्स सेन्चुरी रेयन द्वारा किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। ये तीनों संबद्ध वस्तुओं के एक मात्र उत्पादक हैं।
- (2) जब याचिका दायर की गई थी, उस समय घरेलू उद्योग के पास मेसर्स सेन्चुरी रेयन में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसलिए प्रारंभ में घरेलू उद्योग के आधार का परिकलन, मेसर्स सेन्चुरी रेयन के समग्र उत्पादन के आधार पर किया गया था। बाद में याचिकादाता को समर्थन पत्र प्राप्त होने पर जिसमें मेसर्स सेन्चुरी रेयन के विचाराधीन उत्पाद के सही उत्पादन और बिक्रियों की सही जानकारी निहित थी, एक संशोधित तालिका प्रस्तुत की गई थी। तथापि, उससे घरेलू उद्योग की पात्रता प्रभावित नहीं हुई थी।
- (3) याचिकादाताओं का उत्पादन भारतीय उत्पादन (मेसर्स सेन्चुरी रेयन के समर्थन को शामिल करने और नहीं शामिल करने दोनों के बाद) का एक प्रमुख भाग बनता है और इसलिए नियमावली में उल्लिखित घरेलू उद्योग की परिभाषा के भीतर उसे “घरेलू उद्योग” माना जाना चाहिए।
- (4) याचिकादाता ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और इसके अतिरिक्त वह नियम 2 (घ) की परिभाषा के भीतर चीन में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा प्रयोक्ता से भी संबंधित नहीं है।
- (5) एक हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दायरे से प्रमुख उत्पादक, मेसर्स सेन्चुरी रेयन के बाहर होने के संबंध में संदेह प्रकट किया है, लेकिन यह प्रश्न अप्रासंगिक है क्योंकि मेसर्स केसोराम रेयन, जो कि मेसर्स किंगनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक यूनिट है और मेसर्स इंडियन रेयन, जो कि मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक यूनिट है, दोनों वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ नियमावली के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग हैं।

##### **घ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) घरेलू उद्योग के सबसे बड़े संघटक, मेसर्स सेन्चुरी रेयन के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।
- (2) इस प्रकार याचिका में एक प्रमुख उत्पादक को शामिल नहीं किए जाने के कारण जांच को समाप्त कर दिया जाए।
- (3) मेसर्स सेन्चुरी रेयन के ब्यौरे प्रस्तुत करने से मनाही करने से यह स्पष्ट होगा कि घरेलू उद्योग अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए घरेलू उद्योग के संघटकों को अपनी इच्छा से चुन रहा है।
- (4) जांच शुरू करने की अधिसूचना में आवेदक उद्योग को मेसर्स केसोराम रेयन और मेसर्स इंडियन रेयन के बतौर उल्लिखित किया गया है, जब कि आवेदक के निवेदन में मेसर्स किंगनेट इंडस्ट्रीज और मेसर्स इंडियन रेयन को आवेदकों के रूप में उल्लिखित किया गया है।

**घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

23. आवेदन-पत्र मेसर्ज केसोराम रेयन, जो कि मेसर्ज किंगनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक यूनिट है और मेसर्ज इंडियन रेयन, जो कि मेसर्ज ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक यूनिट है द्वारा प्रस्तुत किया गया है और मेसर्ज इंडियन रेयन द्वारा इसका समर्थन किया गया है।

24. कुल घरेलू उत्पादन में आवेदकों का अंशदान 54% बनता है और मेसर्ज इंडियन रेयन के समर्थन से कुल घरेलू उत्पादन में आवेदकों का अंशदान 100% बनता है, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं किया है और वह नियम 2 (घ) की परिभाषा के भीतर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा प्रयोक्ता से भी संबंधित नहीं है।

**भारतीय उत्पादन**

क्रमांक	विवरण	यूनिट	अवधि			
			2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि
1	याचिकादाता कंपनियां					
क	इंडियन रेयन	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	113	115	118
ख	केसोराम रेयन	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	94	108	87
ग	याचिकादाता कंपनियों का योग	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	108	113	110
2	समर्थक कंपनी – सेन्चुरी रेयन	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	103	114	119
क	कुल भारतीय उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	105	114	114
3	याचिकादाता कंपनियों का हिस्सा	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	108	113	110
4	समर्थक कंपनी का हिस्सा	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	103	114	119
5	याचिकादाता कंपनियों और समर्थक कंपनी का हिस्सा	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	105	114	114
<b>हिस्सा</b>						
6	याचिकादाता कंपनियां		2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि
क	इंडियन रेयन		41%	44%	41%	42%
ख	केसोराम रेयन		15%	14%	15%	12%
ग	याचिकादाता कंपनियों का योग		56%	57%	56%	54%



7	समर्थक कंपनी – सेन्चुरी रेयन		44%	43%	44%	46%
क	कुल भारतीय उत्पादन		100%	100%	100%	100%
8	याचिकादाता कंपनियों का हिस्सा		56%	57%	56%	54%
9	समर्थक कंपनी का हिस्सा		44%	43%	44%	46%
10	याचिकादाता कंपनियों और समर्थक कंपनी का हिस्सा		100%	100%	100%	100%

25. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उचित जांच करने के बाद प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है और वह घरेलू उद्योग बनता है।

### **ऊ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे**

#### **ऊ.1 घरेलू उद्योग के विचार**

26. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिकादाता ने यह स्पष्ट अधिसूचित किया है कि उसने उन्हीं सूचनाओं की गोपनीयता का दावा किया है, जो कि नियमावली के अंतर्गत स्वीकार्य हैं और याचिकादाताओं ने इसका विस्तृत सारांश प्रस्तुत किया है कि उसके बाद आवश्यक सूचना की गोपनीयता का दावा क्यों किया गया है।
- (2) हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदन-पत्र की अगोपनीय वृत्तान्त की प्रमाणिकता के बारे में आरोप लगाया है, लेकिन पक्षकार ऐसे दावों को सिद्ध करने में विफल रहे हैं और ये पूर्णतया सामान्य हैं, जिनका वर्तमान जांच में कोई महत्व नहीं होना चाहिए।
- (3) निर्यातकों द्वारा निर्यातक की प्रश्नावली के अपने उत्तरों में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है और उनके उत्तरों में विभिन्न सूचनाओं की कमी है, जिनका उल्लेख संबंधित मुद्दों में नीचे किया गया है।

#### **ऊ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

27. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों/निर्यातकों/आयातकों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिका के अगोपनीय वृत्तान्त में उसमें निहित आरोपों को उचित ढंग से समझने की कमी है और यह हितबद्ध पक्षकारों को समग्र जांच में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने से रोकती है।
- (2) याचिका में प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण आंकड़ों को अगोपनीय वृत्तान्त में विधिवत् सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

#### **ऊ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

28. नियम 6 (7) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण करने के लिए एक सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध कराया है।

29. पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 में सूचना की गोपनीयता के बारे में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है :-

“गोपनीय सूचना – (1) नियम 7 के उप-नियम (1), (2), (3) और (7) और नियम 14 के उप-नियम (2), नियम 17 के उप-नियम (4) और नियम 19 के उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

30. गोपनीयता के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जितना प्रासंगिक समझा गया था, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार उनका निदान कर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने कारोबार से संबंधित सूचना को गोपनीय माना है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय वृत्तान्त को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है।

### च. जांच शुरू करने से संबंधित मुद्दे

#### च.1 घरेलू उद्योग के विचार

31. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) यह निवेदन किया जाता है कि अधिप्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर मामले को शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र पर्याप्त रूप से अधिप्रमाणित था।
- (2) उसने क्षति का विश्लेषण करने के लिए जरूरी विभिन्न आर्थिक प्राचलों और साथ ही संभावित प्राचलों के संबंध में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं।
- (3) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने भी विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि पाटन-रोधी शुल्क विगत 10/11 वर्षों से लागू है और यह कि शुल्क को जारी रखने के लिए कोई विशिष्ट स्थिति विद्यमान नहीं है। इस नोट पर यह निवेदन किया जाता है कि हालांकि कानूनन 11 वर्षों से क्षति विद्यमान है, लेकिन वस्तुतः यह विगत निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान शुल्क के रूप में परिवर्तन करने के पश्चात प्रभावी हुई है। विगत 5 वर्षों में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार आने से इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त याचिकादाताओं ने अपने निवेदनों में ऐसी विशिष्ट घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिनमें शुल्क को 10 वर्षों से भी अधिक समय तक जारी रखा गया है और जिससे यह सिद्ध होता है कि शुल्क की अवधि को बढ़ाने के लिए समय कभी भी तर्क नहीं रहा है। साथ ही यह भी निवेदन किया जाता है कि निर्यातकों की ओर से प्रवंचना करने की कार्रवाई, वर्तमान मामले में विशिष्ट परिस्थिति में की जानी है और इसलिए ऐसी समस्त संभावना है कि आयात गहून होंगे जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

#### च. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

32. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिका नियमावली के नियम 7 में और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 09 दिसंबर, 2013 के व्यापार सूचना संख्या 19/1/2013 में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है।
- (2) याचिकादाता सामान्यतया यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है और इसलिए जांच को गलत ढंग से शुरू किया गया है।
- (3) घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में जांच अवधि के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्राचलों की सूचना निहित नहीं है। ऐसी सूचना नहीं होने से निर्यातक जांच शुरू करने के आधार को नहीं समझ पा रहे हैं।
- (4) याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत सूचना, नियमावली के नियम 5 (3) के अंतर्गत जांच शुरू करने को यथोचित ठहराने के लिए अपर्याप्त है।
- (5) याचिका के वर्णन में यूनिट कीमत, कुल लागत, निवेशों, रोजगार और भंडार पर सूचीबद्ध आंकड़ों का स्पष्ट रूप से उल्लेख और विश्लेषण नहीं किया गया है, जिसमें सार्थक विश्लेषण की कमी है।
- (6) पाटन-रोधी शुल्क 10 वर्षों से निरंतर जारी है और जांच के वर्तमान तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पाटन-रोधी शुल्क को जारी रखने का कोई विशेष/आपवादिक परिस्थिति नहीं है।

#### च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में पहले से ही यह उल्लेख किया है कि वर्तमान जांच, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्रस्तुत विधिवत् प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर शुरू की जा रही है।

### छ. विभिन्न मुद्दे

#### छ. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे

34. प्राधिकारी को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से निवेदन प्राप्त हुए थे जिनकी प्रतिकृति नीचे प्रस्तुत की गई है:-

- (1) मेसर्ज करुणाल टेक्सटाईल्स
- (2) मेसर्ज गुरु फैब्रिक्स
- (3) मेसर्ज हरिओम इंटरनेशनल
- (4) मेसर्ज श्री सहजाननंद टेक्सटाईल्स
- (5) मेसर्ज प्रकाश टेक्सटाईल्स
- (6) मेसर्ज शिव बलवंत राय रोटरीवाला
- (7) मेसर्ज पटेल प्रवीण कुमार मगनलाल हफ
- (8) मेसर्ज राम इंटरप्राइज
- (9) मेसर्ज शिव टेक्सटाईल्स
- (10) मेसर्ज डेनिश टेक्सटाईल्स
- (11) मेसर्ज मुकुन्द टेक्सटाईल्स
- (12) मेसर्ज श्री जलराम टेक्सटाईल्स
- (13) मेसर्ज सौरभ टेक्सटाईल्स
- (14) मेसर्ज लिबर्टी ट्रेड्स लिमिटेड
- (15) मेसर्ज गुरु फैब्रिक्स
- (16) मेसर्ज हर्षा टेक्सटाईल्स
- (17) मेसर्ज रंजीत फैब्रिक्स
- (18) मेसर्ज मुकेश बलवंतराय रोटरीवाला
- (19) मेसर्ज बाटसन्स टेक्सटाईल्स
- (20) मेसर्ज एस. के. बीविंग प्राईवेट लिमिटेड
- (21) मेसर्ज ईशवर कृपा टेक्सटाईल्स
- (22) मेसर्ज सोनेल सिल्क कार्पोरेशन
- (23) मेसर्ज पटेल दशरथलाल मगनलाल
- (24) मेसर्ज रीघन फैशन प्राईवेट लिमिटेड
- (25) मेसर्ज पटेल अमृतलाल मगनलाल हफ
- (26) मेसर्ज कृष्णा सेल्स कार्पोरेशन
- (27) मेसर्ज ऊर्जा एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
- (28) मेसर्ज बिट्टू सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
- (29) मेसर्ज केटीसी श्रेड एलएलपी
- (30) मेसर्ज वैजू फैब्रिक्स
- (31) मेसर्ज रिकेश टेक्सटाईल्स
- (32) मेसर्ज तेजोदय डाईंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स

- (33) मेसर्ज मनोहर केपिटल मार्केट लिमिटेड
- (34) मेसर्ज जे. एम. टेक्सटाईल्स
- (35) मेसर्ज श्री गिरनार फैब्रिक्स
- (36) मेसर्ज हिमज्योति इंडस्ट्रीज
- (37) मेसर्ज सिल्क पोली फैब
- (38) मेसर्ज सचिन इंडस्ट्रियल को-ओपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड
- (39) मेसर्ज फेडरेशन ऑफ गुजरात बीवर वेल्फेयर एसोसिएशन
- (40) मेसर्ज सुप्रभात प्रिंट प्राईवेट लिमिटेड
- (41) मेसर्ज सुपर्व श्रेड्स

35. उपरोक्त पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) क्षति होने अथवा तथा आगे पाटन और क्षति होने की संभावना निराधार है।

## **छ. 2 प्राधिकारी द्वारा जांच**

36. प्राप्त हुए निवेदनों के उत्तर में प्राधिकारी ने उपरोक्त पक्षकारों को पत्र जारी करके आयातक की प्रश्नावली के संपूर्ण ब्यौरों के साथ उत्तर और अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने को कहा था, जो कि उनके दावे को सिद्ध करने के लिए अनिवार्य होंगे। तथापि, उपरोक्त पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार ने ऐसा नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप उनके दावे निराधार हो गए हैं।

## **ज. बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**

### **नियमावली के अंतर्गत सामान्य मूल्य**

37. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1) (ग) के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

### **ज.1 घरेलू उद्योग के विचार**

38. घरेलू उद्योग द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) अभिगमन नयाचार का एक प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को वर्तमान जांच में चीन के उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन करने वाले उत्पादकों के रूप में माना जाना चाहिए।

- (ख) वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच अवधि अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 (12 महीनों) तक की है। क्षति की जांच अवधि में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच अवधि को शामिल किया गया है।
- (ग) जांच अवधि निर्धारित करने का प्रयोजन ऐसी अवधि पर विचार करना है, जब पाटन के कारण क्षति होने का दावा किया गया है और वह सिद्ध हो गया है। निर्धारण की तारीख, घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति होने के विवादित प्रश्न से संबद्ध नहीं है। चूंकि जांच अवधि के आधार पर घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति होने के तथ्य की संपुष्टि हो गई है, इसलिए केवल जांच अवधि के दौरान प्रचलित दशाओं को इस प्रयोजनार्थ प्रासंगिक, उपयुक्त और आवश्यक माना जाना चाहिए।
- (घ) चीन के उत्पादकों को इस कारणवश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचालन कर रही कंपनियां माने जाने की आवश्यकता है कि चीन में लागतें और कीमतें बाजार प्रतिबलों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। अनुबंध-1 के पैरा 8 में ऐसे प्राचल विनिश्चित हैं, जिन पर बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को स्वीकृत करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इनमें यह भी समाविष्ट है कि जब तक इन दशाओं को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक चीन की लागतों और कीमतों को अपनाया नहीं जा सकता है।
- (ङ) चूंकि चीन की कंपनियों को दिसंबर, 2016 तक अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित कारणों से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए याचिकादाता का निवेदन है कि चीन के उत्पादकों को तब तक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों माने जाने की आवश्यकता है, जब तक कि जांच अवधि में अभिगमन संधि नयाचार में विनिश्चित अवधि को शामिल नहीं कर लिया जाता है।
- (च) नियम 2 (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि किसी घरेलू उत्पादक अथवा किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए आयातों की जांच, जांच अवधि के संदर्भ में की जाती है। यदि केवल जांच अवधि, आधार के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक है, तो वह सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए।
- (छ) चीन के उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के परिवेश में प्रचालन कर रही कंपनियों के बतौर माने जाने की आवश्यकता है और प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।
- (ज) तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण, इस कारणवश नहीं किया जा सकता है कि संबद्ध सूचना उपलब्ध नहीं है। याचिकादाता ने विधिवत् समायोजित भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने का दावा किया है।
- (झ) चीन से पाटन मार्जिन न केवल सार्थक है, बल्कि पर्याप्त भी है। इस प्रकार इससे भारत में विचाराधीन उत्पाद के सार्थक पाटन होने की संपुष्टि होती है। पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद समग्र वर्तमान क्षति अवधि में चीन से आयात की मात्रा सार्थक बनी हुई है।
- (ञ) पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में चीन में उत्पादकों के पास उपलब्ध उत्पाद क्षमताओं और उनके अत्यधिक निर्यातोन्मुखी होने को ध्यान में रखते हुए पाटन निरंतर जारी रहेगा तथा यह और अधिक गहन होगा।
- (ट) एक हितबद्ध पक्षकार ने यह आरोप लगाया है कि याचिकादाता सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त कार्य-प्रणाली प्रदान करने में विफल रहे हैं। लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि इसके ब्यौरे आवेदन-पत्र में दिए गए हैं।

## ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं:-

- (क) 11 दिसंबर, 2016 के बाद सभी निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत किया जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था की प्रश्नावली जारी करना, भेदमूलक है और यह विश्व व्यापार संगठन के चीन अभिगमन नयाचार के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के दायित्वों का उल्लंघन है।
- (ख) भारत को चीन को पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश की मान्यता प्रदान करने के लिए संबद्ध करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए और संबद्ध घरेलू विनियमों में संशोधन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चीन के खिलाफ पाटन-रोधी जांच में "प्रतिनियुक्त देश" के प्रस्ताव को भी समाप्त कर देना चाहिए।
- (ग) याचिकादाताओं ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का परिकलन करने के लिए अपनाई गई कार्य-प्रणाली का प्रकटन नहीं किया है।

## ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

40. अभिगमन नीति नयाचार में अनुच्छेद 15 में उल्लिखित व्यवस्था निम्नानुसार है:-

“गॉट 1994 के अनुच्छेद 6, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटन-रोधी करार”) और एससीएम करार, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश में चीन मूल के होने वाले आयातों से संबंधित कार्रवाई पर लागू होते हैं, जिनमें निम्नोक्त शामिल हैं:-

(क) गॉट 1994 के अनुच्छेद 6 और पाटन-रोधी करार के अंतर्गत कीमत में तुलनीय क्षमता का निर्धारण करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश, जांच अधीन उद्योग के लिए या तो चीन की कीमतें या जांच अधीन उद्योग के लिए लागतों या एक ऐसी कार्य-प्रणाली जो कि घरेलू कीमतों से कड़ी प्रतिस्पर्धा पर आधारित नहीं है या निम्नलिखित नियमों पर आधारित चीन में लागतों का उपयोग करेगा:-

- (1) यदि जांच अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हैं कि उक्त उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित हैं, तो विश्व व्यापार संगठन का आयातक देश कीमत में तुलनीय क्षमता का निर्धारण करने के लिए चीन की कीमतें अथवा जांच अधीन उद्योग के लिए लागतों को प्रयुक्त करेगा।
- (2) विश्व व्यापार संगठन का आयातक देश ऐसी कार्य-प्रणाली प्रयुक्त कर सकता है, जो कि चीन में घरेलू कीमतों या लागतों की कड़ी तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांच अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते हैं कि उक्त उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित नहीं हैं।

(ख) यदि विश्व व्यापार संगठन के आयातक देश की राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत यह प्रमाणित हो जाता है कि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जायेंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य देश की राष्ट्रीय विधि में अभिगमन की तारीख को बाजार अर्थव्यवस्था का मानदंड निहित हो। किसी भी स्थिति में उप-पैरा (क) (2) के प्रावधान अभिगमन की तारीख से 13 वर्षों के बाद समाप्त हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि चीन विश्व व्यापार संगठन के आयातक देश की राष्ट्रीय विधि के अनुसरण में यह प्रमाणित कर देता है कि एक विशिष्ट उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित हैं, तो उप-पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उक्त उद्योग या क्षेत्र पर बिल्कुल लागू नहीं होंगे।”

(ग) विश्व व्यापार संगठन के आयातक सदस्य को उप-पैराओं के अनुसार (क) पाटन-रोधी पद्धतियों संबंधी समिति और (ख) आर्थिक सहायता और प्रतिकारी उपायों संबंधी समिति को प्रयुक्त कार्य-प्रणालियों को अधिसूचित करना होगा।

(घ) विश्व व्यापार संगठन के आयातक सदस्य की राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत चीन द्वारा यह प्रमाणित कर दिए जाने पर कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, उप-पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त हो जायेंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य की राष्ट्रीय विधि में अभिगमन की तारीख को बाजार अर्थव्यवस्था का मानदंड निहित हो। किसी भी स्थिति में उप-पैरा (क) (2) के प्रावधान, अभिगमन की तारीख के 15 वर्षों के बाद समाप्त हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि विश्व व्यापार संगठन के आयातक सदस्य की राष्ट्रीय विधि के अनुसरण में चीन यह प्रमाणित करता है कि किसी विशिष्ट उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित हैं, तो उप-पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उक्त उद्योग अथवा क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।”

41. अनुच्छेद 15 में यह समाविष्ट है कि चीन के अभिगमन की तारीख से 15 वर्ष बाद उप-पैरा का एक प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इस पैरा के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं। चूंकि जांच अवधि के आधार पर पाटन के कारण घरेलू उद्योग की क्षति के तथ्य की पुष्टि हो गई है, इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि के दौरान प्रचलित दशाएं प्रासंगिक, उपयुक्त और आवश्यक हैं। वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक की है। चूंकि जांच की प्रमुख अवधि के दौरान अनुच्छेद 15 का उप-पैरा विद्यमान था, इसलिए यदि जांच अधीन उत्पादक यह स्पष्ट नहीं दर्शा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उक्त उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री करने के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित नहीं हैं, तो प्राधिकारी एक ऐसी कार्यप्रणाली प्रयुक्त करेंगे जो कि चीन में घरेलू कीमतों और लागतों के साथ कड़ी तुलना पर आधारित नहीं है।

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों में भारत और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा चीन जनवादी गणराज्य को पाटन-रोधी जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है, बशर्ते कि नियमावली के अनुसार निर्यातक अथवा किसी विशिष्ट निर्यातक द्वारा ऐसी अवधारणा का खंडन नहीं किया जाता है।

**ज.3.1 बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच**

43. पाटन-रोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

- (क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;
- (ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे-खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;
- (ग) इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं, जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- (घ) विनिमय दर का परिवर्तन व्याज की दर पर किया जाता है।

44. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी एमईटी के दावों की पर्याप्तता का निर्धारण करने में बाध्य हैं। इस प्रकार चाईना चेम्बर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी और चाईना केमिकल फाईबर्स एसोसिएशन के तर्कों को अस्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जनवादी गणराज्य के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उचित समझते हैं।

**ज.3.2 चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**

45. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ अनुबंध-1 के पैरा-7 को ध्यान में रख कर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। भारत में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित संबद्ध उत्पादों के सामान्य मूल्य की संरचना, प्रमुख कच्चे माल के लिए घरेलू उद्योग के अनुकूलतम खपत मानकों को ध्यान में रख कर की गई है और कच्चे माल की लागत, घरेलू उद्योग के लिए स्वीकृत स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, परिवर्तन लागत, ब्याज, एसजीए आदि के अनुसार है। उचित लाभ के लिए ब्याज रहित बिक्रियों की लागत के 5% की अनुमति दी गई है।

**ज.3.3 निर्यात कीमत का निर्धारण****ज.3.3.1 घरेलू उद्योग के विचार**

46. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) मेसर्ज किसनकिसयांग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड के संदर्भ में याचिकादाता ने यह निवेदन किया है कि निर्यातक ने प्रश्न क. 5 के अपने उत्तर में यह बताया है कि उसकी कोई भी संबंधित अथवा सहायक कंपनी संबद्ध उत्पाद का उत्पादन अथवा बिक्री करने में नहीं लगी हुई है। तथापि, मेसर्ज किसनकिसयांग बेईलू इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड ("बेईलू") किसनकिसयांग की धारक कंपनी है, जो कि संबद्ध उत्पाद का निर्यात में संलिप्त है।
- (2) यह नोट किया जाता है कि निर्यातक अपनी निर्यातक प्रश्नावली में संबद्ध सूचना देने में विफल रहा है। इस कार्य में विफल होने से समग्र समूह की निबल निर्यात कीमत का पता लगाने में कार्य-प्रणाली प्रभावित होती है। इसके अनुसार प्राधिकारी मेसर्ज किसनकिसयांग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करना उपयुक्त समझते हैं।

**ज.3.3.2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

- (1) याचिकादाता निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य-प्रणाली का प्रकटन करने में विफल रहा है।
- (2) चीन से निर्यातकों ने सहयोग दिया है और इसलिए निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण, इन निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में चीन में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

- (क) जिलिन केमिकल फाईबर स्टॉक कंपनी लिमिटेड
- (ख) जिलिन एन्का विस्कोस कंपनी लिमिटेड
- (ग) जिविन हीस्ट फाईबर कंपनी लिमिटेड
- (घ) किसनकिसआंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड

48. किसनकिसआंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड के संदर्भ में याचिकादाता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि निर्यातक ने प्रश्न क. 5 के अपने उत्तर में यह बताया है कि उसकी कोई भी संबंधित अथवा सहायक कंपनी संबद्ध उत्पाद का उत्पादन अथवा बिक्री करने में नहीं लगी हुई है। तथापि, मेसर्स किसनकिसआंग बेईलू इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड ("बेईलू") किसनकिसआंग की धारक कंपनी है, जिसने संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है।

49. निर्यातक ने बताया है कि बेईलू सहायक कंपनियों में से केवल एक्ससीएफ विस्कोस फिलेमेंट यार्न का उत्पादन करती है और भारत में विस्कोस फिलेमेंट यार्न का निर्यात करती है। निर्यातक ने बताया है कि बेईलू स्वयं विस्कोस फिलेमेंट यार्न का उत्पादन अथवा बिक्री नहीं करती है। निर्यातक ने यह भी बताया है कि वह वर्ष 2016 के लिए बेईलू के लाभ विवरण और बेईलू के राजस्व लेखाओं के प्रायोगिक अधिशेष प्रस्तुत करेगा जो दर्शाएगा कि बेईलू ने विस्कोस फिलेमेंट यार्न से कोई राजस्व अर्जित नहीं किया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने इस संबंध में संबद्ध दस्तावेजों को उनके प्रमाणित अनुवाद के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसा नहीं किए जाने से समग्र समूह की निबल निर्यात कीमत का पता लगाने की कार्य-प्रणाली प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में प्राधिकारी उसके लिए पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं।

50. उत्तरों की जांच करने के बाद डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों की जांच की गई है। निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को सत्यापित किया गया था और जांच करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली के परिशिष्ट-वार उत्तर को ध्यान में रखा गया था।

51. प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के अन्य (असहयोगी) उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजीसीआईएंडएस के कारोबार-वार आंकड़ों के आधार पर किया है। तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य से सभी निर्यातकों के संबंध में कारखाना-गत स्तर पर भारित औसत निबल निर्यात कीमत का निर्धारण, श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के आधार पर समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पतन व्ययों और अंतरदेशीय भाड़े के लिए उचित समायोजन करने के बाद किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

**ज.3.4 पाटन मार्जिन का निर्धारण**

52. पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए भारत को निर्यात कीमत (प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सभी समायोजनों का निबल) की तुलना सामान्य मूल्य के साथ की गई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

**ज.3.5 पाटन मार्जिन**

53. संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण, संरचित सामान्य मूल्य और निबल निर्यात कीमत की तुलना करके किया गया है। संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए परिकलित पाटन मार्जिन नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

क्रमांक	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (अमरीकी \$/मी.टन)	निर्यात कीमत -(अमरीकी \$/मी.टन)	पाटन मार्जिन (अमरीकी \$/मी.टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन सीमा- %
1.	किसनकिसआंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
2.	जिविन हीस्ट फाईबर लिमिटेड कापेरेशन	***	***	***	***	1-10
3.	जिलिन केमिकल फाईबर स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	(1-10)
4.	जिलिन एन्का विस्कोस	***	***	***	***	(1-10)



	कंपनी लिमिटेड					
5.	शेष श्रेणी	***	***	***	***	(20-30)

### झ. क्षति का मूल्यांकन तथा क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच करने की कार्यप्रणाली

#### क्षति और कारणात्मक संबंध

##### झ.1 घरेलू उद्योग के विचार

54. वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान क्षति के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) जांच अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग/प्रत्यक्ष खपत में वृद्धि हुई है। पाटन-रोधी शुल्क के बावजूद भारत में समग्र रूप से और उत्पादन/खपत दोनों रूप में संबद्ध देश से आयात सार्थक बने हुए हैं।
- (2) आयातों की पहुंच कीमत (मूल सीमा-शुल्कों को शामिल करने के बाद) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से अत्यधिक कम है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक कीमत कटौती हो रही है। इन परिस्थितियों में यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में और कटौती करेंगे जो कि अत्यधिक सीमा तक कीमत में वृद्धि होने की रोकथाम करेंगे।
- (3) चीन से आयातों की पहुंच कीमत वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग की लागत से कम है।
- (4) कुल आयातों में संबद्ध देश आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है।
- (5) ऐसा माना जाता है कि यदि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण करेंगे।
- (6) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के कारण संबद्ध आयातों के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, संबद्ध आयातों के बाजार का हिस्सा, अभी भी बहुत अधिक बना हुआ है।
- (7) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है। एक याचिकादाता ने सीएसवाई के लिए अपनी क्षमता बढ़ाई है और दूसरी कंपनी ने एसएसवाई के लिए अपनी क्षमता बढ़ाई है। देश में उत्पाद की वर्तमान और भावी मांग को ध्यान में रखते हुए क्षमता में विस्तार पूर्णतया यथोचित है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।
- (8) घरेलू उद्योग ने उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न प्रोद्योगिकियों के आधार पर प्राचलों का विश्लेषण किया है। एसएसवाई की प्रोद्योगिकी के संबंध में यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग लाभ अर्जित करता हुआ प्रतीत होता है। इसको छोड़ कर पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के निरपेक्ष घरेलू उद्योग को घाटे हो रहे हैं।
- (9) तथापि, कीमत में कटौती के स्तर को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातित उत्पाद की मांग में पर्याप्त रूप से वृद्धि होगी। इससे घरेलू उत्पाद की मांग में प्रत्यक्ष गिरावट आने का स्पष्ट पता चलेगा, जो कि संभवतः घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आने के फलस्वरूप होगी।
- (10) जांच अवधि के दौरान लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ जैसे कीमत प्राचलों के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन ने भी सुधार दर्शाया है।
- (11) अत्यधिक पाटित आयातों की मौजूदगी के फलस्वरूप निरंतर पाटन होगा जिसके कारण पाटन-शुल्क लागू नहीं होने से क्षति की पुनरावृत्ति होगी।
- (12) वर्तमान जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक और अत्यधिक हैं।
- (13) घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत में अंतर को देखते हुए यदि इस स्थिति में वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दे दी जाती है, तो याचिकादाता का निवेदन है कि घरेलू उद्योग को तुरंत वित्तीय घाटे होने शुरू हो जायेंगे।
- (14) पाटन-रोधी शुल्क के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए, यदि पाटन-रोधी शुल्क की निम्नतर राशि पर भी विचार किया जाता है, तो भी आयातों की पहुंच कीमत में 20 रुपए प्रति किलोग्राम से भी अधिक गिरावट आ जाएगी। वर्तमान जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ इस स्तर से कम है। इससे स्वतः पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे होंगे।
- (15) संबद्ध देश में निर्यातकों के पास क्षमताओं और उनके निर्यातानुमुखी होने को ध्यान में रखते हुए यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दे दी जाती है, तो संभवतः आयात तीव्र हो जायेंगे।
- (16) पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

- (17) पाटन-रोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है। उपाय के रूप को निर्धारित मात्रा में अमरीकी डालरों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

## अ.2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

55. वर्तमान जांच में एक पक्षकार ने क्षति के बारे में पृथक् से निवेदन किए हैं और उनमें उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं:-
- (1) घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन स्थिर रहा है अथवा विभिन्न आर्थिक प्राचलों के संबंध में उसमें सुधार हुआ है।
  - (2) क्षति होने अथवा पाटन और क्षति के बढ़ने की संभावना का आरोप निराधार है।
  - (3) घरेलू उद्योग को हुई कोई भी क्षति, क्षति चीन जनवादी गणराज्य से आयातों से भिन्न कारकों के कारण हुई है।
56. इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सुनवाई के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने अपने उत्तरों और लिखित निवेदनों में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:-
- (1) याचिकादाता यह प्रमाणित करने में बिल्कुल विफल रहे हैं कि संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है।
  - (2) वर्तमान परिस्थितियों में नकारात्मक कीमत कटौती और नकारात्मक क्षति मार्जिन है।
  - (3) भारत में एसएसवाई प्रोद्योगिकी से परिष्कृत डेनियर्स और उत्कृष्ट परिष्कृत डेनियर्स उत्पादित किए जाते हैं। जहां एसएसवाई उत्पाद को शामिल किया जाता है, वहां प्रपत्र-4-क में प्रदत्त क्षति के आर्थिक प्राचलों से यह ता चलता है कि घरेलू उद्योग अच्छी स्थिति में है। इसलिए यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित परिष्कृत डेनियर्स और उत्कृष्ट परिष्कृत डेनियर्स, चीन से आयातित डेनियर्स से प्रतिस्पर्धी हैं।
  - (4) वर्तमान भारतीय बाजार की खपत, धीरे-धीरे अपरिष्कृत डेनियर्स से परिष्कृत डेनियर्स में अंतरित हो रही है।
  - (5) विभिन्न आर्थिक प्राचलों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है और चीन से आयातों के फलस्वरूप घरेलू उद्योग पर कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।
  - (6) घरेलू उद्योग के क्षति विश्लेषण से समान उत्पाद के उप-सेट को एक मात्र इस कारणवश बाहर रखे जानी की अनुमति नहीं है कि उनका उत्पादन, विभिन्न प्रोद्योगिकियों द्वारा किया जा रहा है।
  - (7) भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अविवेचित संरक्षण के फलस्वरूप एकाधिकरण होगा और इसका जन हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
  - (8) अधिकतर आवेदक कंपनियों ने अनेक वर्षों से अपनी प्रोद्योगिकी को उन्नत नहीं बनाया है।
  - (9) घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय मानक की कोटि के यार्न की आपूर्ति करने में अक्षम है।

## अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

57. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों को नोट कर लिया है। प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति की उचित ढंग से जांच की है।
58. क्षति नहीं होने के निवेदनों के संबंध में उल्लेखनीय है कि नीचे किया गया क्षति विश्लेषण यह सिद्ध करने के लिए स्वतः स्पष्ट है कि क्या पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा नहीं।
59. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की कार्यवाई के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका निदान निम्नानुसार किया गया है।
60. प्राधिकारी ने मात्रा और कीमत दोनों के प्रभाव की जांच की है। क्षति का निर्धारण करने में इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।
61. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

62. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी प्राचल गिरावट दर्शाएं। कुछ प्राचल गिरावट दर्शा सकते हैं, जब कि कुछ प्राचल सुधार दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षति के सभी प्राचलों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष देते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने तथ्यों और निवेदनों में दिए गए तर्कों को ध्यान में रख कर क्षति के प्राचलों की सार्थक रूप से जांच की है।

### अ.3.1 द्वारा पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

#### (क) मांग और बाजार का हिस्सा

63. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योगफल के रूप में वर्णित किया है। इस प्रकार से मूल्यों

#### मांग और बाजार का हिस्सा

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि
<b>मांग</b>					
घरेलू उद्योग की विक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
समर्थक कंपनी की विक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
चीन से आयात	मी.टन	18,781	16,094	9,862	10,261
अन्य देशों से आयात	मी.टन	842	245	11	26
<b>कुल मांग</b>	<b>मी.टन</b>	<b>47,169</b>	<b>45,429</b>	<b>44,113</b>	<b>41,963</b>
<b>मांग में बाजार का हिस्सा</b>					
घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	31.64%	35.50%	43.24%	40.18%
समर्थक कंपनी का हिस्सा	%	26.76%	28.53%	34.38%	35.30%
चीन जनवादी गणराज्य का हिस्सा	%	39.82%	35.43%	22.36%	24.45%
अन्य देशों का हिस्सा	%	1.79%	0.54%	0.02%	0.06%
<b>कुल</b>	<b>%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है।

65. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है, जब कि संबद्ध देश के आयातों के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, हालांकि यह अभी भी अधिक है।

66. अन्य देशों के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है।

**(ख) आयातों की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा**

67. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की आयातों की मात्रा का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

**आयात और बाजार का हिस्सा**

विवरण	मापन का यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	128	113
समर्थक कंपनी की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	120	117
संबद्ध देश – चीन से आयात	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	53	55
अन्य देशों से आयात	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	29	1	3
कुल आयात	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	50	52
कुल खपत	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	94	89
कुल भारतीय उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	114	114
निम्नोक्त के संबंध में संबद्ध देश से आयात :-					
कुल आयात	%	96%	99%	100%	100%
उत्पादन	%	65%	53%	30%	31%
खपत	%	40%	35%	22%	24%

68. क्षति अवधि के दौरान भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयातों के बाजार के हिस्से में अत्यधिक कमी हुई है, जो कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बाजार के हिस्से से घट कर लगभग आधा रह गया है।

69. भारत में संबद्ध वस्तुओं की खपत में गिरावट आई है।

**अ.3.2 पाटित आयातों के कीमत प्रभाव और उसका घरेलू उद्योग पर प्रभाव****(क) कीमत-कटौती**

70. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे

आयातों के प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक मात्रा में ह्रास करते अथवा कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकते, जो कि अन्यथा अत्यधिक सीमा तक हो जाती।

71. इस संबंध में घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों के निबल के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की कीमत का निर्धारण कारखाना-गत स्तर पर किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ की है।

#### कीमत-कटौती

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
निबल बिक्री वसूली	रूपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	107	114
<b>चीन</b>					
पाटन-रोधी शुल्क रहित पहुंच कीमत	रूपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	103	102
कीमत-कटौती	रूपए/किग्रा	***	***	***	***
कीमत-कटौती %	%	-11.29%	-2.12%	-8.01%	-0.87%
पाटन-रोधी शुल्क सहित पहुंच कीमत	रूपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	103	102
कीमत-कटौती	रूपए/किग्रा	***	***	***	***
कीमत-कटौती %	%	-15.55%	-6.82%	-12.43%	-5.63%

72. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में निबल बिक्री वसूली में 14% तक की वृद्धि हुई है।

73. आधार वर्ष की तुलना में पहुंच कीमत में भी मामूली वृद्धि हुई है।

74. ऐसा प्रतीत होता है कि शून्य कीमत-कटौती हुई है।

#### (ख) कम कीमत पर बिक्री

75. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमत पर बिक्री किए जाने की भी जांच की है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत के साथ की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

#### कम कीमत पर बिक्री

विवरण	यूनिट	जांच अवधि
		चीन जनवादी गणराज्य
क्षति रहित कीमत	रूपए/मी.टन	***
पहुंच मूल्य	रूपए/मी.टन	***
कम कीमत पर बिक्री	रूपए/मी.टन	***

कम कीमत पर बिक्री का %	%	***
कम कीमत पर बिक्री की सीमा %	% सीमा	(0-10)

76. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण नकारात्मक कम कीमत पर बिक्री हुई है।

#### **पाटित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभाव**

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात, घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अत्यधिक स्तर पर कीमत ह्रास हुआ है और कीमत में वृद्धि करने में रूकावट आई है, जो कि सामान्य स्थिति में अन्यथा अत्यधिक सीमा तक हो जाती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तन पर विचार किया है। इसकी स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

#### **कीमत ह्रास और न्यूनीकरण**

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
उत्पादन की लागत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	104	110
निबल बिक्री वसूली	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	107	114
पाटन-रोधी शुल्क रहित पहुंच कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	103	102
पाटन-रोधी शुल्क सहित पहुंच कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	103	102

78. उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट पता चलता है कि विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य ने वृद्धि होने की प्रवृत्ति दर्शाई है।

79. आधार वर्ष की तुलना में उत्पादन की लागत में 10% तक और निबल बिक्री वसूली में 14% तक की वृद्धि हुई है।

#### **अ.3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक प्राचलों की जांच**

80. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-11 में उल्लिखित प्रावधान में क्षति का निर्धारण करने में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच करना निहित है। इसके अतिरिक्त नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और सूचकों का तथ्य परक और निष्पक्ष जांच करना शामिल है, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही इनमें बिक्रियों में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूचियां, रोजगार, वेतन, संवृद्धि और पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता भी शामिल है।

81. तदनुसार घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक प्राचलों का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है।

#### **(क) क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग**

82. उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	101	100
संयंत्र का उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	106	103
उत्पादन - विचाराधीन उत्पाद	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	110
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	105	103

83. यह देखा जा सकता है कि समग्र क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

84. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग ने भी वही प्रवृत्ति दर्शाई है, जो कि उत्पादन की रही है।

**(ख) बिक्रियों की मात्रा**

85. मात्रा और कीमतों दोनों के रूप में बिक्रियों के प्राचल निम्नानुसार हैं:-

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	128	113
घरेलू बिक्रियां	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	137	129
बिक्री कीमत - घरेलू	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	107	114
निर्यात बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	171	114
निर्यात बिक्रियां	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	143	103
बिक्री कीमत - निर्यात	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	84	90
कुल बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	129	113
कुल बिक्रियां	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	137	128

86. यह नोट किया जाता है कि समग्र क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की मात्रा में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

87. बिक्री कीमत भी स्थिर बनी रही है और क्षति अवधि में उसमें धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

(ग) **बाजार का हिस्सा**

88. घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

**मांग में बाजार का हिस्सा**

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि
<b>मांग में बाजार का हिस्सा</b>					
घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	31.64%	35.50%	43.24%	40.18%
समर्थक कंपनी का हिस्सा	%	26.76%	28.53%	34.38%	35.30%
चीन जनवादी गणराज्य का हिस्सा	%	39.82%	35.43%	22.36%	24.45%
अन्य देशों का हिस्सा	%	1.79%	0.54%	0.02%	0.06%
कुल	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

89. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है, जब कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के कारण संबद्ध देश के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है।

90. अन्य देशों से आयातों के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है।

(घ) **माल सूचियां**

91. संबद्ध वस्तुओं की मालसूची से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:-

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि
औसत सटॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	188	148	83
माल सूची प्रति दिवस	मी.टन/ दिवस	3	5	4	2
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	188	148	83

92. उपरोक्त से यह नोट किया जाता है कि मालसूची प्रति दिवस बहुत अधिक नहीं है और क्षति अवधि के दौरान उसमें धीरे-धीरे कमी हो रही है।

(ङ) **लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह**

93. घरेलू उद्योग के लाभ/हानि, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि
बिक्रियों की लागत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***



प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	104	110
विक्री कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	107	114
लाभ/(हानि)	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	507	446	534
लाभ/(हानि) - कुल	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	548	570	603
मूल्यहास	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	187	193	223
नकदी लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	197	195	208
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ सीमा %	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	187	175	130

94. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता के प्राचलों में सुधार हुआ है।

95. इसी प्रकार ब्याज पूर्व लाभ, नकदी लाभ तथा निवेश पर प्रतिलाभ ने भी सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है।

**(च) रोजगार, वेतन और उत्पादकता**

96. रोजगार, वेतन और उत्पादकता की स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	102	109
वेतन	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	121	125
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	111	101
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.टन/दिवस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समग्र क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता से संबंधित आंकड़ों में निरंतर सुसंगत सुधार हुआ है।

**(छ) संवृद्धि**

विवरण	वाईओवाई	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि
उत्पादन	%	-	7.69	5.36	(3.37)
घरेलू बिक्रियों की मात्रा	%	-	8.09	18.27	(11.60)
बिक्रियों की लागत	%	-	3.12	0.82	5.68
बिक्री कीमत	%	-	6.95	0.24	6.23
लाभ/हानि प्रति यूनिट	%	-	406.91	(12.02)	19.69

98. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि मांग में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग ने लाभ में वृद्धि होने, सुगम नकदी प्रवाह होने और निवेश पर प्रतिलाभ में वृद्धि होने की आशा की थी। तथापि, संबद्ध देश से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग उसे वांछित स्तर पर प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है।

99. तालिका से पता चलता है कि अनेक प्राचलों में घरेलू उद्योग की संवृद्धि सकारात्मक रही है, जबकि जांच अवधि में उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है।

**(ज) पाटन की मात्रा**

100. पाटन की मात्रा एक ऐसा संकेतक है जिससे यह पता चलता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को किस सीमा तक क्षति हो सकती है। विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देश के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम है।

**पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता**

101. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कोई सत्यापित सूचना नहीं है और न ही ऐसी सूचना रिकार्ड पर उपलब्ध है जिससे यह पता चल सकता हो कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मौजूदगी से क्षेत्र में भावी निवेश बिगड़ सकता है।

102. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षेत्र के लिए पूंजीगत निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित नहीं हो सकती है।

**अ.3.4 क्षति पर निष्कर्ष**

103. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में समग्र रूप से कमी हुई है। ऐसी सार्थक कमी भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत के संबंध में देखी गई है।

104. जांच से पता चलता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में मामूली कमी आई है। यह भी नोट किया जाता है संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की वसूली से अधिक है। घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को वहां 14% तक बढ़ाने में समर्थ रहा है, जहां क्षति अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत में 10% तक की वृद्धि हुई है, जैसा कि पैरा 77 की तालिका में देखा गया है।

**ब. क्षति मार्जिन की मात्रा**

105. जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से निर्यातकों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्रमांक	उत्पादक/निर्यातक	क्षति रहित कीमत (अमरीकी \$/मी.टन)	पहुंच मूल्य (अमरीकी \$/मी.टन)	क्षति मार्जिन (अमरीकी \$/मी.टन)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन सीमा- %
1.	क्सिनक्सिआंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
2.	जिविन हीस्ट फाईबर लिमिटेड कापेरिशन	***	***	***	***	5-15

3.	जिलिन केमिकल फाईबर स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	(0-10)
4.	जिलिन एन्का विस्कोस कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	(0-10)
5.	शेष श्रेणी	***	***	***	***	(25-35)

#### ट. पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना

106. प्राधिकारी का मानना है कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का केन्द्र बिन्दु इसकी जांच करना है कि यदि कोई वर्तमान क्षति नहीं होती है, तो पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की अनुमति देने की स्थिति में क्या निरंतर पाटन होने और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

#### ट.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

107. पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के अपने दावे के समर्थन में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) जांच अवधि के दौरान सार्थक पाटन मार्जिन से प्रमाणित होता है कि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन के निरंतर जारी रहने और तीव्र होने की संभावना है। समग्र क्षति अवधि के दौरान पाटन विद्यमान था। साथ ही बिगत पाटन-रोधी जांच के दौरान भी अत्यधिक पाटन विद्यमान था। इसके फलस्वरूप यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की पूरी संभावना है।
- (2) पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ अत्यधिक नकारात्मक हो जाएगा।
- (3) आयात की कीमतें वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उपभोक्ता आयातित उत्पाद की ओर प्रवृत्त होंगे जिसके फलस्वरूप उत्पाद के आयातों में अत्यधिक वृद्धि होगी। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी बिक्री कीमतों को घटाना होगा और वे बिक्रियों की लागत से भी कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होंगे जिसके फलस्वरूप उन्हें विकट कीमत क्षति होगी।
- (4) भारत में प्रमुख निर्यातक के संबंध में पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत कटौती अन्य की तुलना में बहुत अधिक है। विभिन्न तृतीय देशों के निर्यातकों के संबंध में सामूहिक मार्जिन अत्यधिक और सकारात्मक है।
- (5) भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। उपभोक्ता अपनी अधिप्राप्ति का निर्णय लेने में कीमत को सर्वाधिक महत्व देते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में संबद्ध देश से कम कीमत के आयातों की उपलब्धता निश्चित रूप से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन होने और घरेलू उद्योग को उसकी परिणामी क्षति के निरंतर जारी रहने/बढ़ने की संभावना है।
- (6) मूल जांच और सभी परवर्ती जांच में अत्यधिक पाटन के विद्यमान होना प्रमाणित हो गया है। वर्तमान अवधि में भी पाटन मार्जिन अत्यधिक है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है कि उत्पादक तीव्रता से पाटन करने लगेंगे और उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- (7) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बाद भी आयातों की मात्रा अत्यधिक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त चीन में उत्पादकों की विद्यमान क्षमताओं और उनके विस्तार को ध्यान में रखते हुए तथा प्रवंचना के उनके कार्यों से स्पष्ट पता चलता है कि चीन के उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र भारतीय मांग को हथियाने में सक्षम हैं।
- (8) प्रवंचना के कार्यों से संबद्ध देश से उत्पादकों के संभावित व्यवहार का स्पष्ट पता चलता है। इससे संबद्ध देश में उत्पादकों के पास अत्यधिक वेशी क्षमता उपलब्ध होने के कारण संबद्ध वस्तुओं का पाटन करने के लिए उत्पादकों की घोर आवश्यकता प्रमाणित होती है।
- (9) उत्पादक अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमताओं का उपयोग, अपने उत्पादों का भारत में अधिक निर्यात और पाटन करने के लिए करेंगे।
- (10) सीसीएफ समूह की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के विभिन्न संयंत्रों को बंद करना निराधार कल्पना मात्र है और प्रमुख उत्पादक अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।

- (11) चीन से विचाराधीन उत्पाद के अत्यधिक निर्यात तृतीय देशों को किए जा रहे हैं। इन देशों को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद की कीमतें अत्यधिक कम हैं और इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप ऐसे कम कीमत के निर्यात भारत को अपवर्तित हो जायेंगे।
- (12) घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति दुर्बल है और पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को घाटे होने की संभावना है और वह वापस ऐसी स्थिति में चला जाएगा जो कि मूल जांच के समय में प्रचलित थी।
- (13) वर्तमान मात्रा स्वतः पाटन और क्षति की संभावना को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों के तीव्र होने की निश्चित संभावना है।
- (14) पृथक निर्यात कारोबार में क्षति मार्जिन निर्धारित करने और तदनुसार ऐसे कारोबार पर विचार करने की आवश्यकता है, जहां क्षति मार्जिन और कीमत कटौती सकारात्मक है।
- (15) निर्यातकों के ये आरोप कि वीएफवाई निर्यातकों के लिए भारत एक प्रमुख बाजार नहीं है, मात्र झूठे आरोप हैं और इनका खंडन सीसीएफ समूह की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदत्त सूचना से किया जा सकता है। रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत ऐसे 4 (चार) शीर्षस्थ बाजारों में से एक है, जहां निर्यातक पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी अपने उत्पाद को बेचते हैं।

## **ट.2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन**

108. विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) क्षति का आरोप अथवा पाटन और क्षति के बढ़ने की संभावना निराधार है।
- (2) पर्यावरण संरक्षण की चिंताओं और कामगारों के परिश्रमिक में वृद्धि होने तथा अत्यधिक पूंजीगत निवेश की आवश्यकता के कारण भविष्य में चीन में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।
- (3) वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2015 में चीन में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन क्षमता कम है, जिसका मुख्य कारण वीएफवाई के विभिन्न उत्पादन संयंत्रों का निरंतर बंद होना है।
- (4) भारत को निर्यात कम हो रहे हैं और भारत अब चीन के उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों के लिए बढ़ता हुआ बाजार नहीं रहा है।
- (5) भारत चीन के मूल के विस्कोस फिलेमेंट यार्न का प्रमुख लक्षित बाजार नहीं है।
- (6) वर्तमान भारतीय बाजार में खपत धीरे-धीरे अपरिष्कृत डेनियर्स से परिष्कृत डेनियर्स में अंतरित हो रही है।
- (7) घरेलू उद्योग की क्षमता और प्रोद्योगिकी भारतीय बाजार की मांग को पूरा नहीं कर सकती है।
- (8) चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध उत्पाद के संबंध में किसी भी अन्य देश ने कभी भी पाटन-रोधी, प्रतिकारी और सुरक्षा के उपाय क्रियान्वित नहीं किए हैं।
- (9) संबद्ध उत्पाद के सबसे बड़े उत्पादक की सूचना पर विचार किए बिना क्षति की संभावना को कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
- (10) घरेलू उद्योग के विभिन्न प्राचलों में सुधार होने के कारण वर्तमान जांच में क्षति के निरंतर जारी रहने की कोई संभावना नहीं है।
- (11) विगत निर्णायक समीक्षा जांच में जिन प्राचलों के आधार पर शुल्क को जारी रखा गया था, उनमें से कोई भी प्राचल इस समीक्षा में विद्यमान नहीं है।
- (12) घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अर्थात् अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक क्षति और पाटन की संभावना का कोई दावा नहीं किया है।
- (13) घरेलू उद्योग का यह दावा सही नहीं है कि चीन अन्य देशों को कम कीमतों पर निर्यात कर रहा है क्योंकि संयुक्त विश्लेषण से असंगत परिणाम निकलेंगे।
- (14) सीसीएफ की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि निर्यातक अपने निर्यातों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह विस्तार और इस तथ्य को नहीं दर्शाती है कि अन्य उत्पादक उत्पादन बंद कर रहे हैं। साथ ही यह भी दर्शाती है कि मौजूदा क्षमता में कोई नया संवर्धन नहीं है।

### ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

109. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध 2 (7), निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ 2017 (346) ई.एल.टी. 328 (गुजरात) के मामले में दिनांक 13.12.2016 के निर्णय के साथ पठित नियमावली के अनुबंध 2 के अनुच्छेद (7) के अनुसार आर्थिक क्षति के खतरे के विशिष्ट संदर्भ में पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने और पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच की है।

**(क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि होने की अत्यधिक दर से पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना का पता चलता है।**

110. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग अथवा निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से जांच अवधि पश्चात कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

111. इसके अतिरिक्त निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के भाग-2 में उल्लिखित रूप में और तरीके से तृतीय देश के कारोबार-वार निर्यात आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।

112. इससे प्राधिकारी जांच अवधि पश्चात संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के निरंतर पाटन को समर्थक सांख्यिकीय साक्ष्य के साथ प्रमाणित करने के लिए बाध्य हैं।

113. इसके अतिरिक्त वर्तमान मामले में इस तर्क को कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से निरंतर पाटित आयातों के कारण निरंतर क्षति होती रहेगी, निम्नलिखित कारणों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है:- (क) जैसा कि क्षति विश्लेषण और प्रमुख आर्थिक प्राचलों की जांच करने पर पूर्ववर्ती पैराओं से पता चलता है, वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान किसी भी प्रमुख आर्थिक प्राचल में क्षति नहीं हो रही है और (ख) जांच अवधि पश्चात क्षति होने के दावों के लिए कोई सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**(ख) किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य अथवा आसन्न निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होने से भारतीय बाजारों में बढ़ते पाटित निर्यातों की संभावना का पता चलता है**

114. आर्थिक क्षति के खतरे का पता लगाने के लिए इस प्राचल के लिए मौजूदा बेशी क्षमताओं और क्षमता संवर्धन, यदि कोई हुआ है, का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि भारतीय बाजार में प्रयोज्य मात्रा के अपवर्तन की संभावना का पता लगाया जा सके। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देश से उत्पादक पहले से अत्यधिक क्षमताओं का सामना कर रहे हैं।

115. इसके अतिरिक्त ये उत्पादक अनेक देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं, जिसमें से अत्यधिक निर्यात पाकिस्तान के संबंध में कम कीमतों पर किए जा रहे हैं। इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क को वापस लेने की स्थिति में भारत को ऐसे निर्यातों को अपवर्तित कर दिए जाने की संभावना का पता चलता है। इस तर्क को भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग और खपत के समर्थन से यथोचित नहीं ठहराया जा सका है। यह नोट करना आवश्यक है कि समग्र क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग और खपत में वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती पैराओं में किए गए मांग और खपत के अध्ययन ने गिरावट होने की प्रवृत्ति दर्शाई है।

116. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा बेशी क्षमताओं और भारतीय बाजार में बढ़े हुए पाटित निर्यातों की परिणामी संभावना/संभावितता के बारे में कोई सत्यापन करने योग्य साक्ष्य और सूचना प्रदान नहीं की है।

**(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसे घरेलू कीमतें अत्यधिक ह्रास होंगी अथवा उन पर न्यूनीकरण होने का प्रभाव पड़ेगा तथा अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना होगी।**

117. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के मामले में समग्र क्षति अवधि अथवा जांच अवधि के दौरान भारत में वर्तमान पहुंच कीमत से कोई कीमत कटौती नहीं हुई है।

**(घ) वस्तु की माल सूचियों की जांच की जा रही है।**

118. रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों में जांच की जा रही वस्तु की माल सूचियों पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य निहित नहीं है।

**(ङ) संबद्ध देश से उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु की प्रवंचना।**

119. पहले यह आरोप लगाया गया है कि निर्यातक ने “कशीदाकारी के यार्न” के नाम पर भारत में संबद्ध वस्तु की प्रवंचना की है। इसके अतिरिक्त यह भी आरोप लगाया गया है कि स्पष्टीकरण के बावजूद निरंतर शुल्क की अपवंचना की जा रही है। यह नोट किया जाता है कि शुल्क की अपवंचना एक पृथक जांच है, जिसका निदान उपयुक्त मंच पर किया जा सकता है। प्रवंचना का कथित कार्य, भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटन करने के इरादे को स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं कर सकता है।

**उ. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध**

120. धारा 9 क (5) के अंतर्गत प्राधिकारी को पाटन और क्षति होने की संभावना तथा इस पर ध्यान दिए बिना कि समीक्षा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात हुआ है अथवा नहीं, शुल्कों को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता की जांच करना अपेक्षित होता है।

121. इसकी जांच की गई है कि क्या पाटन-रोधी नियमावली में सूचीबद्ध अन्य प्राचल घरेलू उद्योग की क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इनका उल्लेख निम्नानुसार है:-

**(क) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

122. प्राधिकारी ने कारोबार-वार आधार पर डीजीसीआईएंड से प्राप्त संबद्ध वस्तुओं के आयात आंकड़ों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। तथापि, चूंकि वर्तमान जांच, निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए वर्तमान जांच में नए देशों को शामिल नहीं किया जा सकता है।

**(ख) मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन, घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

**(ग) प्रोद्योगिकी में विकास**

124. प्रोद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

**(घ) व्यापार की प्रतिबंधित पद्धतियां तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

125. व्यापार की ऐसी कोई प्रतिबंधित पद्धति नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ सकता है। देश में कच्चे माल के साथ-साथ संबद्ध वस्तुओं का आयात करने की स्वतंत्रता है।

**(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

126. प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के केवल घरेलू प्रचालनों को ध्यान में रख कर क्षति विश्लेषण किया गया है। इसलिए निर्यात बाजार में कार्य-निष्पादन ने वर्तमान क्षति विश्लेषण को प्रभावित नहीं किया है।

**(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता**

127. यह नोट किया जाता है कि इस अवधि में उत्पादन प्रति कर्मचारी के साथ-साथ उत्पादन प्रति दिवस के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

128. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर जांच की कार्रवाई के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एकत्रित, विश्लेषित और प्रमाणित जांच के अनिवार्य तथ्यों का एतद्वारा हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन किया जाता है, ताकि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित अनुसार इन तथ्यों पर अपनी टिप्पणियां देने में सक्षम हो सकें।

**ड. घरेलू उद्योग/ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के पश्चात निवेदन****घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन**

129. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :-

- i. याचिकाकर्ता इस बात को समझने में असमर्थ है कि क्या पीसीएन- वार विश्लेषण सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए किया गया था।
- ii. प्राधिकारी पूर्व वर्षों से जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर इसके प्रभाव के बीच सह संबंध पर विचार नहीं कर पाए हैं।
- iii. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के बारे में प्राधिकारी का विश्लेषण अनुपयुक्त और अपर्याप्त है और इस पर अधिक उद्देश्यपरक जांच किए जाने की जरूरत है।
- iv. ऐसा लगता है कि प्राधिकारी ने पीसीएन पर विचार किए बिना ही कीमत कटौती का निर्धारण किया है। यदि इस पर विचार किया गया होता तो यह देखा जाता कि ऐसी वस्तुओं जो बड़ी मात्रा में निर्यात की गई हैं के संबंध में कीमत कटौती सकारात्मक है।

- v. कम कीमत पर बिक्री का निर्धारण भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसके निर्धारण के लिए पीसीएन- वार विश्लेषण पर विचार नहीं किया गया है।
- vi. याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए संगत अनुरोध की जांच की जानी चाहिए ताकि व्यक्तिगत निर्यात सौदों पर विचार किया जा सके और उन्हें कम कीमत कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय सकारात्मक और नकारात्मक रूप में पृथक् किया जा सके।
- vii. प्राधिकारी ने एनआईपी और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है और यह निरमा लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है।
- viii. याचिकाकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित विचारी उत्पाद की पुष्टि करते हैं।
- ix. विचाराधीन उत्पाद की दायरे के संबंध में निर्यातकों द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।
- x. किसी भी निर्यातक ने अपने वैश्विक निर्यातों के सौदा वार विवरण प्रदान नहीं किए हैं क्योंकि यह (क) तीसरे देश में पाटन (ख) भारतीयबाजा की तुलना में अन्य बाजारों की कीमत आकर्षकता (ग) निर्यातकों के व्यवहार का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है।
- xi. वे अपनी निर्यात अभिमुखता के लिए कारणों में एक कारण यह है कि उन्हें प्राप्त प्रोत्साहनों के संबंध में कोई सूचना प्रदान करने से बचते हैं।
- xii. चूंकि कोई भी सूचना प्रदान नहीं की गई है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियामावली के नियम 6 (8) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकूल अनुमान निकालना है।
- xiii. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंधों के लिए किए गए महत्वपूर्ण निवेदन को पूरी तरह से नजर अंदाज किया गया है और इसीलिए अनुपयुक्त निर्धारण किया गया है।
- xiv. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग आशा के अनुसार वृद्धि नहीं कर पाया है और यह संबद्ध देशों से आयातों के कारण है।
- xv. घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन खराब रहा है और यदि पाटन रोधी शुल्क हटाने की अनुमति प्रदान की जाती है तो उसे काफी हानि उठानी होगी।
- xvi. यदि घरेलू उद्योग अपनी मौजूदा कीमतों को रखता है तो शुल्क हटाने की अवस्था में घरेलू उद्योग को बिक्री की मात्रा की हानि होगी जिससे घरेलू उद्योग के लाभ व विकास को हानि होगी।
- xvii. चीन की क्षमताओं और उनके वर्तमान विस्तार तथा निर्यातकों की पाटनरोधी शुल्क को दरकिनार करके भी वस्तुओं को पाटन करने की प्रकृति/व्यवहार पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि चीन के उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के लिए समूची भारतीय मांग को दरकिनार करने में सक्षम हैं।
- xviii. पैरा 113 में प्राधिकारी की टिप्पणी अनुपयुक्त है क्योंकि इसमें उद्देश्यपरक विश्लेषण का अभाव है। इसके अलावा घरेलू उद्योग का वस्तुओं के निष्पादन से यह तात्पर्य नहीं है कि संभावना नहीं है। इसकी बजाय जांच की अवधि में आयातों में मात्र वृद्धि होने से ही घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा और इसकी संभावना रहेगी।
- xix. प्राधिकारी ने चीन के निर्यातकों के विस्तार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा की गई चिंताओं को नजर अंदाज किया है जो कि प्रदान की गई सीसीएफ रिपोर्ट से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग उन्नत हो रहा है और सभी संभावनाओं में दर्शाया गया है जिससे निर्यात भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन करेंगे।
- xx. केवल इस दरकिनार करने की कार्रवाई से ही यह पता चल जाता है कि निर्यातक भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन करने के अति इच्छुक हैं।
- xxi. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति की संभावना से संबंधित मामलों में उठाए गए संगत मसलों पर विचार करने में विफल रहे हैं।
- xxii. मूल और सभी बाद की जांचों में महत्वपूर्ण पाटन होने की संभावना प्रमाणित होती है। वर्तमान अवधि में पाटन मार्जिन भी पर्याप्त है। उत्पादकों द्वारा पाटन में तेजी लाने की संभावना है और इससे घरेलू उद्योग को पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की अवस्था में क्षति होने की संभावना है।

- xxiii. आयातों की मात्रा पाटन रोधी शुल्क प्रवृत्त रहने पर भी काफी रही। इसके अलावा चीन की मौजूदा क्षमताओं और उनके विस्तार तथा उनकी नजर अंदाज करने की कार्रवाई पर विचार करते हुए यह पता चलता है कि चीन के उत्पादकों में विचाराधीन उत्पाद के लिए भारत की समग्र मांग को नजर अंदाज करने की क्षमता है।
- xxiv. नजर अंदाज करने की कार्रवाई संबद्ध देश से उत्पादकों के संभावित व्यवहार को दर्शाती है। इससे उनके पास उपलब्ध भारी सरप्लस क्षमता के कारण संबद्ध देश में उत्पादकों को संबद्ध वस्तुओं का पाटन करने की अति आवश्यकता है।
- xxv. उत्पादकों के पास अधिक्य क्षमताओं को भारत में उनके उत्पाद का आगे निर्यात करने और पाटन करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।
- xxvi. सीसीएफ ग्रुप की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के विभिन्न संयंत्रों को बंद करना मात्र एक परिकल्पना है और प्रमुख उत्पादक अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की प्रक्रिया में है।
- xxvii. चीन से तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद का महत्वपूर्ण निर्यात हो रहा है। इन देशों के उत्पाद की कीमत काफी कम है और पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने से इन कम कीमत के उत्पादों का भारत की ओर रुख हो जाएगा।
- xxviii. मोटे यार्न के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन फाइन और सुपरफाइन उत्पादों की तुलना में सकारात्मक है और ऐसी स्थिति यह दर्शाती है कि विभिन्न उत्पादों के संबंध में निर्यात कीमतें भिन्न होती हैं।
- xxix. कम कीमत कटौती और क्षति मार्जिन नकारात्मक मार्जिन वाले सौदों को छोड़कर निर्धारित किए जाने चाहिए। यह तर्क घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है कि क्षति मार्जिन वर्तमान जांच में निर्धारित नहीं किया जाए।
- xxx. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार आया है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने एनआईपी और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई की है जिसका एक संभावित विश्लेषण से कोई संबंध नहीं है।
- xxxi. शुल्कों का मात्र विश्लेषण कार्यों की स्थिति के लिए संकेतात्मक नहीं है यदि शुल्क आगे लागू नहीं हैं।
- xxxii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े यह दर्शाएंगे कि पाकिस्तान को किया गया निर्यात काफी है और इसके भारत की ओर निर्यात होने की पूरी संभावना है।
- xxxiii. याचिकाकर्ताओं ने चीन में मौजूदा सरप्लस क्षमताओं के संबंध में संगत सूचना प्रदान की है।
- xxxiv. क्षति की संभावना के मापदंड वहां लागू नहीं होते जहां पाटन रोधी शुल्क लागू हैं।
- xxxv. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने "क्षति की संभावना" के साथ "क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना" से समानता की है।
- xxxvi. खपत के संबंध में आयातों की जांच करते समय प्रकटीकरण विवरण यह विचार नहीं करते कि खपत के संबंध में आयातों में वर्ष 2013-14, 2014-15, और 2015-16 के बीच गिरावट आई है। तथापि जांच की अवधि में खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- xxxvii. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री मोटे यार्न के संबंध में काफी अधिक और फाइन व सुपरफाइन यार्न के मामले में नकारात्मक है।
- xxxviii. फाइन व सुपरफाइन यार्न के मामले में कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री इस कारण से नकारात्मक है कि (क) प्राधिकारी ने अपने आप ही निर्धारण की पद्धति में परिवर्तन किया है (ख) यहां तक कि जब मापन की इकाई भार है तो उत्पाद की खपत लम्बाई में है।
- xxxix. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कभी भी घरेलू उद्योग को याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई पद्धति में परिवर्तन करने को स्पष्ट करने के लिए नहीं बुलाया।
- xl. पैरा 77, 78 और 79 के अनुसार जबकि उत्पादन की लागत में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है आयात में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः चीन के उत्पादकों ने लागतों में वृद्धि की तुलना में अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि नहीं की है।
- xli. घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों से जारी क्षति का दावा नहीं किया है जैसाकि प्राधिकारी ने पैरा 113 में टिप्पणी की है।
- xlii. क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना जांच की अवधि के बाद सामग्री क्षति पर बलागू नहीं होती और इसीलिए क्षति की संभावना अथवा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना निर्धारित करने के लिए जांच की अवधि के बाद पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
- xliii. इसके अलावा चूंकि पाटनरोधी शुल्क जांच की अवधि के बाद भी लागू है, इसलिए जांच की अवधि के बाद के डाटा में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना नहीं दर्शाई गई।



- xliv. चूंकि निर्यातकों ने जांच की अवधि के सौदा वार डाटा और अन्य सूचना के लिए प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है इसलिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के लिए कोई प्रतिकूल अर्थ निकालने की बजाय निर्यातकों के लिए प्रतिकूल अर्थ निकालना चाहिए।
- xlv. चूंकि सिगनेट इंडस्ट्रीज का उल्लेख जांचप्रारंभ अधिसूचना में याचिकाकर्ता कंपनी के रूप में किया गया था इसलिए प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि पैरा 130 में यह उल्लेख करे कि उसे तथ्य की जानकारी नहीं थी।
- xlvi. याचिकाकर्ता कंपनियों के व्यौरों के संबंध में कोई सूचना मांगने वाले निदेशालय से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ।
- xlvii. एक याचिकाकर्ता कंपनी के मामले में निर्धारित पूंजी दाखिल सूचना के अनुसार नहीं है और न ही यह निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास दर्ज तथ्य के अनुसार है।

### **निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन**

130. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- i. निर्यातक ने यह दावा किया है कि बैबलू स्वयं विस्कोस फिलामेंट यार्न का उत्पादन अथवा बिक्री नहीं करता है। वर्ष 2016 के लिए बैबलू का लाभ विवरण देखने से बैबलू का वर्ष 2016 के लिए कुल प्रचालन राजस्व केवल सीएनवाई 14,175,120.69 है जो कि इतनी छोटी राशि है और विस्कोस फिलामेंट का उत्पादन करने वाली कंपनी के लिए राजस्व नहीं हो सकता। बैबलू के मुख्य कारोबार राजस्व में पानी, भाप, बिजली, उपस्कर, उपस्कर सहायक सामग्री और श्रम सेवा तथा पट्टे से राजस्व शामिल है। अतः बैबलू स्वयं विस्कोस फिलामेंट यार्न का उत्पादन नहीं करता केवल एक्ससीएफ ही वीएफवाई का उत्पादन करता है और उसे भारत को बेचता है।
- ii. निर्यातक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही।
- iii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया अंतिम जांच परिणाम में सहयोगी उत्पादक निर्यातक का नाम सही करके यिविन हीस्ट फाइबर कंपनी लिमिटेड कारेपोरेशन के स्थान पर मैसर्स याबिन हीस्ट फाइबर कंपनी लिमिटेड किया जाए।
- iv. अंत में यह अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान प्रकटीकरण विवरण में घरेलू उद्योग को किसी उचित कारण के बिना अधिक गोपनीयता की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा प्राधिकारी द्वारा ऐसी गोपनीयता का दावा क्यों किया गया है जबकि कुछ अन्य मामलों में प्राधिकारी ने अपने प्रकटीकरण विवरण में मात्रा संबंधी सूचना प्रकट की है।
- v. प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण विवरण के पैरा 18 में की गई टिप्पणियों को देखते हुए कि वर्तमान समीक्षा का दायरा संशोधित नहीं किया जाएगा हम अपना अनुरोध दोहराते हैं कि प्राधिकारी को पूर्व जांच में निर्धारित उत्पाद दरायरे को बनाए रखना चाहिए।
- vi. जांच के दायरे में कोई संशोधन/ बदलाव जो पूर्व में बिना कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किए की गई थी वर्तमान विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं की जानी चाहिए।
- vii. चीन जन जण, इंडोनेशिया, मलेशिया और थैलैंड से पोलिस्टर स्टेपल फाइबर की हाल ही की जांच में (सं. 14/49/2016-डीजीएडी) पाटनरोधी शुल्क न लगाने का निर्णय लिया जिसका आधार यह था कि भारत में अन्य उत्पादक जो याचिका में शामिल नहीं हुए हैं के पास मांग का सबसे अधिक अंश है और संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जबकि यह उपयोक्ता उद्योग द्वारा दाखिल विभिन्न अनुरोधों की जांच से स्पष्ट है। उस जांच में इस तथ्य के बाद भी कि अन्य उत्पादक को प्राधिकारी द्वारा नियम 2 (ख) के तहत अपात्र उत्पादक माना गया था उसका भाग न लेना जांच के लिए घातक माना गया।
- viii. संबद्ध वस्तु के तीन उत्पादक हैं प्रमुख उत्पादक मैसर्स सैन्चुरी रेयोन जो कुल भारतीय उत्पादन का 46 प्रतिशत उत्पादन करता है ने जांच में भाग नहीं लिया। इसके अलावा मैसर्स सैन्चुरी रेयोन के पास भारत में मांग का लगभग 35 प्रतिशत है। प्रकटीकरण विवरण में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कैसे मैसर्स सैन्चुरी रेयोन का केवल 35 प्रतिशत हिस्सा मांग में है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया जांच को निरस्त करें क्योंकि प्रमुख उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- ix. यह अनुरोध किया जाता है कि एनआईपी की गणना के बारे में घरेलू उद्योग का दावा कानूनी और तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इस प्रसंग में आय कर अधिनियम 1961 की धारा 2 (42सी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो इस प्रकार है :

(42 सी) “मंदी बिक्री” से तात्पर्य व्यक्तिगत परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऐसी बिक्री में प्रदत्त मूल्यों के बिना एक मुश्त रूप से विचार करने के लिए बिक्री के परिणामस्वरूप एक अथवा अधिक उपक्रमों के हस्तांतरण से है।

स्पष्टीकरण। - इस खंड के प्रयोजन के लिए उपक्रम से तात्पर्य खंड (19एए) के स्पष्टीकरण-1 में प्रदत्त तात्पर्य से है।

स्पष्टीकरण 2 – शंका के समाधान के लिए यह घोषणा की जाती है कि स्टांप ड्यूटी पंजीकरण शुल्क अथवा इसी प्रकार के करो व शुल्कों के एकमात्र प्रयोजन के लिए परिसंपत्तियों अथवा देनदारियों के मूल्य का निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए प्रदत्त मूल्यों के रूप में नहीं माना जाए।

- x. यह देखा जा सकता है कि आय कर अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसार “मंदी बिक्री” से तात्पर्य एक या अधिक उपक्रमों का हस्तांतरण करने से है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि “मंदी बिक्री” माध्यम के तहत किसी उपक्रम अथवा कारोबारी क्रियाकलाप की बिक्री को पूर्ण रूप से चिंता माना गया है न कि व्यक्तिगत परिसंपत्ति को। इस प्रसंग में प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III का अवलोकन कर सकता है जिसमें पूंजी पर तर्कसंगत प्रतिफल की परिकल्पना की गई है न कि किसी कारोबारी संस्था के मूल्य की। प्राधिकारी की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार पूंजी पर प्राप्त प्रतिफल अनुमत्य है न कि कारोबारी मूल्य से। अतः घरेलू उद्योग का मंदी बिक्री” मूल्य के संबंध में अधिक प्रतिफल प्राप्त करने का कोई दावा पूरी तरह से गलत है और कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया मूल्यांकन भी असंगत है क्योंकि प्रतिफल की अनुमति केवल परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्यहास मूल्य के आधार पर होती है। वास्तव में यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग का दावा भी इस आधार पर बिना मेरीट के है कि प्रभाव अनुपात केवल परिसंपत्ति के पुनः मूल्यांकन के समान होगा। परिसंपत्ति का ऐसा पुनः मूल्यांकन नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार अनुमत्य नहीं है।
- xi. प्राधिकारी ने यह सही पाया है कि केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मैसर्स सिगनेट इंडस्ट्रीज को बिक्री वास्तव में मूल कंपनी से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को स्थानांतरित करना है और इसीलिए ऐसा कोई लेन देन पाटन रोधी कानूनों की दृष्टि से संगत है।
- xii. हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि कृपया घरेलू उद्योग को निर्धारित परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्यहास के आधार पर परिकलित पूंजी के प्रतिफल की तुलना में कारोबार के मूल्य पर किसी प्रतिफल की अनुमति न देने के अपने रुख को स्पष्ट करें।
- xiii. प्रकटीकरण विवरण से यह स्पष्ट है कि आवेदक उद्योग प्रदत्त मापदंड के संबंध में किसी क्षति का सामना नहीं कर रहा है। इसके प्रतिकूल ये सभी मापदंड सकारात्मक विकासदर्शा रहे हैं और आवेदक उद्योग के स्थिरीकरण को दर्शा रहे हैं।
- xiv. प्राधिकारी ने याचिका दाखिल करते समय केसोराम रेयोन का सिगनेट इंडस्ट्रीज को स्वामित्व हस्तांतरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा गलतबायानी के प्रकटीकरण विवरण के अनुबंध 4 में कई उदाहरणों का उल्लेख किया है। प्रतिवादी प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि जांच शुरुआत करना घरेलू उद्योग की ऐसी गलतबायानी के कारण कानूनन गलत था।
- xv. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार और प्रकटीकरण विवरण के अनुबंध 4 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया के तहत एनआईपी का निर्धारण सही है।
- xvi. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के सभी आर्थिक मापदंडों में सुधार है। कोई कीमत हास/ मूल्यहास नहीं है। इसके अलावा जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक कम कीमत की बिक्री अथवा कीमत कटौती है। जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में गिरावट का कारण मांग में गिरावट का होना है न कि आयातों का होना है।
- xvii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के लिए पाटन का कम मार्जिन निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने पाकिस्तान से भारत को वीएफवाई के निर्यातों का विपथन होने की संभावना और वस्तुओं को दरकिनार करने की संभावना को उचित रूप से अस्वीकार किया है।
- xviii. इस प्रकार से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि वर्तमान में कोई पाटन अथवा क्षति नहीं है और भविष्य में किसी पाटन अथवा क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- xix. घरेलू उद्योग के पास चीन जन. गण. में सरप्लस क्षमताओं के बारे में सूचना प्रदान करने का भार है। प्राधिकारी यह देखे कि घरेलू उद्योग सरप्लस क्षमताओं की मौजूदगी के बारे में साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है।
- xx. वीएफवाई के लिए क्षमता के विस्तार पर चीन जन गण में कानून में कठोर पर्यावरणीय मानक हैं और प्रतिबंध है। उद्योग सूचना मंत्रालय, चीन सरकार द्वारा 2010 में (और 2017) कानूनन संबद्ध उत्पाद की नई क्षमता को शामिल करने पर प्रतिबंध है।
- xxi. रिपोर्ट से पता चलता है कि कई वीएफवाई उत्पादकों ने चीन जन गण में वीएफवाई के उत्पादन को बंद कर दिया है जिसके कारण समग्र क्षमता में कमी आई है। अतः अतिरिक्त क्षमता अथवा सरप्लस क्षमता की आगे कोई संभावना नहीं है जिसके कारण पाटन और क्षति की संभावना हो।

### इ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

131. यह नोट किया जाता है कि प्रकटीकरण उपरांत की अवस्था में प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त संगत पैरा में पहले ही जांच कर ली गई है। तथापि अनुरोध की स्पष्टता को देखते हुए उन पर नीचे उल्लेख किया गया है :

- i. एनआईपी और उत्पादन की लागत का निर्धारण नियमों के प्रावधानों के अनुसार और गणना के लिए निदेशालय में अपनाई जा रही एकसमान प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।
- ii. पीसीएन वार विश्लेषण याचिकाकर्ता और सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त डाटा के लिए किया गया है। क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन पर निष्कर्ष पीसीएन वार डाटा के विधिवत विश्लेषण के बाद किया गया था और उसी का उपयोग भारित औसत निकालने के लिए किया गया था।
- iii. निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण निदेशालय में अपनाई जा रही एक समान प्रक्रिया के अनुसार सबसे अधिक सक्षम घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है।
- iv. संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमतों से कम कीमत पर नहीं किया जा रहा है और संबद्ध देश से कीमत कटौती न केवल जांच की अवधि में बल्कि पूरी क्षति अवधि के दौरान नकारात्मक है।
- v. चीन से कुल आयातों के संबंध में आयातों के अंश में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है उत्पादन व खपत के संबंध में आयात में भी कमी आई है जिसके कारण घरेलू उद्योग का बाजार में अंश बढ़ा है और संबद्ध देश से पाटन द्वारा हुई क्षति में कमी लाने में निबल विक्री प्राप्त हुई है।
- vi. मैसर्स केसोराम रेयोन मैसर्स केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 31.3.2016 तक हिस्सा था। मैसर्स सिगनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रेयोन, केसोराम इंडस्ट्रीज के पारदर्शी पेपर और रासायनिक कारोबार 31.3.2016 को कारोबार समाप्त होने पर अधिग्रहण किया है। तदनुसार सिगनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच रेयोन, पारदर्शी पेपर और रासायनिक कारोबार उपक्रम के हस्तांतरण के लिए एक मंद विक्री माध्यम आधार पर कुल 541 करोड़ रुपए मूल्य पर एक हस्तांतरण करार हस्ताक्षरित किया गया है। कारोबारी हस्तांतरण करार में दिनांक 27 मई 2016 को संशोधन किया गया जिसमें पक्षकारों के बीच यह सहमति थी कि 31 मई 2016 तक कारोबार का समापन हो जाना चाहिए। तदनुसार केआईएल ने दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016 तक की दो माह की अवधि के लिए मैसर्स सिगनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से कारोबार किया। क्रेता सिगनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाद में दिनांक 7 मई 2016 को विक्रेता केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी बन गई।
- vii. जांच के दौरान यह पाया गया कि मैसर्स केसोराम रेयोन की प्रमाणित बैलेंसशीट के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को निर्धारित परिसंपत्तियों का मूल्य 45.72 करोड़ रुपए था। तथापि मैसर्स सिगनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उसी तारीख को 427.13 करोड़ रुपए का निर्धारित परिसंपत्ति मूल्य दर्शाया है।
- viii. बाद के व्यौरों में यह दर्शाया गया है कि मूल्य का निर्धारण एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया था। चूंकि सिगनेट इंडस्ट्रीज केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है इसलिए रिटर्न के प्रयोजन से परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यांकन नहीं किया गया। क्योंकि इससे सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुबंध-III का उल्लंघन होता। अनुबंध-III के पैरा 4 (xiii) के अनुसार उत्पाद के लिए लगी औसत पूंजी पर एक तर्कसंगत रिटर्न की अनुमति ब्याज, कारपोरेट टैक्स और लाभ की वसूली के लिए अनुमत्य है। दोनों याचिकाकर्ता कंपनियों की निबल निर्धारित परिसंपत्ति किसी पुनः मूल्यांकन के बिना अपनाई गई हैं।
- ix. सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुबंध-III के पैरा viii में अन्य के साथ साथ यह कहा गया है निर्धारित परिसंपत्तियों के पुनः मूल्यांकन के प्रभाव को पूंजी की गणना में विचार नहीं किया जाएगा।
- x. प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों पर भी ध्यान दिया है क्योंकि पाटन रोधी शुल्क दिनांक 24 मई 2006 से प्रवृत्त है।
- xi. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की राय की जांच की है ताकि पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की जा सके जिसमें नियमावली के अनुबंध II (vii) दिनांक 13.12.2016 को निर्णीत निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ 2017 (346) ई एल टी 328 गुजरात के साथ पठित नियमावली के अनुबंध-II के खंड vii के अनुसार सामग्री क्षति की संभावना पर विशेष बल दिया है। यह दोहराया जाता है कि प्राधिकारी ने क्षति की संभावना के साथ क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की बराबरी नहीं की है। क्षति की संभावना का आधार पूरी क्षति अवधि के दौरान आर्थिक मापदंडों के आधार विश्लेषण करना नहीं है। यह रिकार्ड में सबसे बेहतर तथ्य है। भविष्य में क्षति की संभावना विश्वव्यापी साक्ष्य के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित नहीं की गई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी का प्रकटीकरण उपरांत का अनुरोध उसी पूर्वानुमान और गणना पर आधारित है जिससे प्राधिकारी को क्षति की संभावना की उद्देश्यपरक जांच की थी।
- xii. घरेलू उद्योग और सहयोगी निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोधों में कोई तारतम्य नहीं है। जहां हितबद्ध पक्षकारों, चीन सरकार से विशेष प्रतिनिधियों ने यह दावा किया है कि चीन में निर्माण इकाइयां संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पर्यावरणीय कारणों से बंद की

जा रही हैं उसी समय याचिकर्ता से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसमें क्षमता विस्तार के लिए चीन सरकार की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि सरप्लस क्षमताओं के आधार पर पाटित आयातों की संभावना और उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है।

- xiii तीसरे देश के निर्यातों और निर्यातों की स्टॉक इन्वेन्ट्री से यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया और अपेक्षित डाटा प्रदान नहीं किया। घरेलू उद्योग ने तीसरे देश के निर्यात डाटा प्रस्तुत किए हैं जिनकी जांच की गई है। यह उत्पाद भारत और पाकिस्तान दोनों को विभिन्न उत्पादों में निर्यात किया गया है। भारत की मांग के साथ मेल नहीं कहा जा सकता। अतः भारत को निर्यातों का विपथन होने का भय आधारहीन है।
- xiv. विभिन्न आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह सुधार मुख्यतः लागू पाटनरोधी उपायों के कारण से है। अतः पाटनरोधी उपायों ने अपेक्षित प्रयोजन को पूरा किया है जिससे निर्यातकों द्वारा उनका उत्पाद पाटित किए जाने से अनुचित फायदा उठाने में कमी आई है।
- xv. प्राधिकारी यह भी दोहराते हैं कि भारत पाटनरोधी उपायों को लागू करने के लिए निष्कर्ष निकालने हेतु कम शुल्क नियम का अनुसरण करता है। चूंकि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है इसलिए पाटनरोधी व्यापार उपचारी उपायों को केवल पाटन के आधार पर नहीं बढ़ाया जा सकता।

#### ढ. निष्कर्ष

132. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की वर्तमान समीक्षा जांच पूरी करने पर प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देश से निर्यातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई बड़ी क्षति नहीं हो रही है। इसके अलावा शुल्को को समाप्त किए जाने के कारण क्षति की संभावना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का कोई कारण नहीं है। उपरोक्त निष्कर्ष के अनुसार प्राधिकारी का यह विचार है कि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का उल्लेख करते हुए कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क दिनांक 24 मई 2006 से मौजूद है इसलिए प्राधिकारी का यह विचार है कि मौजूदा पाटन रोधी शुल्क से अपेक्षित प्रयोजन पूरा हो गया है।

133. इस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20<sup>th</sup> April, 2018

#### Final Findings

**Subject: Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of Viscose Filament Yarn originating in or exported from China PR.**

**F. No. 15/16/2016/DGAD:** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

1. Whereas having regard to the above Act and the Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an antidumping investigation against import of Viscose Filament Yarn originating in or exported from China PR vide Notification No.14/23/2004-DGAD on 7<sup>th</sup> April, 2005. The Authority notified final findings on 4<sup>th</sup> April, 2006 recommending imposition of definitive duties on imports of Viscose Filament Yarn originating in and exported from China. The definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from the subject country were imposed by the Department of Revenue vide Customs Notification No. 45/2006 dated 24<sup>th</sup> May, 2006.

2. The imposition of duty has been reviewed from time to time and the Mid Term Review Final Finding was notified by the Authority vide Notification No. 15/8/2007 - DGAD dated 22<sup>nd</sup> May, 2009 recommending continued imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. As per the recommendations of the Authority, the anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 81/2009-Customs dated 13<sup>th</sup> July, 2009.

3. After the sunset review conducted at the behest of the petitioner requesting for change in the continuation of antidumping duty the Authority notified final findings recommending change in the form of anti-dumping duty vide Notification No. 15/23/2010-DGAD dated 24<sup>th</sup> February 2012. The anti-dumping duty was in force in accordance with Notification No. 23/2012-Customs dated 4<sup>th</sup> May, 2012.
4. Whereas, in terms of the Act and the Rules, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.
5. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
6. And whereas, M/s. Kesoram Rayon, a unit of Cygnet Industries Ltd. & M/s Indian Rayon, a unit of Grasim Industries Limited (hereinafter also referred to as “Petitioners” or “Applicants”) filed an application in the present case before the Designated Authority ( hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules for initiating sunset review of the anti-dumping duty on imports of Viscose Filament Yarn (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) and requested for extension of existing quantum of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
7. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant to justify initiation of sunset review investigation issued a public notice vide Notification No. 10/2017-DGAD dated 24<sup>th</sup> April, 2017 to examine whether the expiry of the said duties on the import of the above goods originating or exported from the subject country is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to 3<sup>rd</sup> May, 2018 vide Custom Notification No. 14/2017, dated 3<sup>rd</sup> May, 2017.
8. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from China PR.

### **PROCEDURE**

9. Procedure described below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:
  - i. The Authority notified the Embassies/Representatives of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
  - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
  - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
  - iv. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from China to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from China PR.
  - v. The Authority sent Exporter’s Questionnaire and Market Economy Questionnaire to elicit relevant information to the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
    - a. Yibin Grace Co. Ltd.
    - b. Jilin Chemical Fibre Group Co. Ltd.
    - c. Jilin Enka Viscose Co. Ltd.
    - d. Yibin Heist Fibre Co. Ltd.
    - e. Hangzhou B.P. Chemical Fibre Co.
    - f. Boading Swan Group
    - g. Xinxiang Bailu Chemical Fibre
  - vi. In response to the above notification, few exporters have responded or submitted questionnaire responses. The following exporters responded to the exporter’s questionnaire:
    - a. Jilin Chemical Fiber Stock Co. Ltd.

- b. Jilin Enka Viscose Co. Ltd.
  - c. Yibin Hiest Fibre Co. Ltd.
  - d. Xinxiang Chemical Fibre Co. Ltd.
- vii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- a. Shah Trading Co.
  - b. Vyapar Com & Industries Ltd.
  - c. Yash Enterprises
  - d. Doriwala Industries
  - e. Marwadi Brothers
  - f. Rajmal Son's and Group
  - g. Chunnilal Kundanmall
  - h. Shanti Textiles
  - i. Krishan Sales Corporation
  - j. Bittu Synthetics Pvt. Ltd.
  - k. Amrit Rayon
- viii. None of the above mentioned importers of the subject goods has filed any questionnaire response in this matter. However, two importers of subject goods namely, M/s. Reagan Fashions Pvt. Ltd and Liberty Trendz Pvt. Ltd. have responded to the Initiation Notification and have filed importer's questionnaire response.
- ix. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- x. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- xi. The Non-Injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xii. The Authority held an oral hearing on 16th March, 2018 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6), which was attended by the representatives of domestic industry only. The representatives of domestic industry who presented their views orally at the time of oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally at the time of oral hearing.
- xiii. On the spot verification of the data of the domestic industry was carried out to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this finding.
- xiv. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is April, 2016 to March, 2017 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods April 2013-March 2014, April 2014-March 2015, April 2015-March 2016 and the POI.
- xv. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this disclosure statement.
- xvi. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

- xviii. A Disclosure Statement was issued on 10.04.2018 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 17.04.2018 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately
- xix. ‘\*\*\*’ in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.67.95 = 1 US\$.

## **PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

### **Submissions of the Domestic industry**

10. The views of the domestic industry are as follows:

- i. The present review investigation is a sunset investigation. The product involved in the original investigation and in the present sunset review investigation is Viscose Rayon Filament Yarn upto 150 deniers (and +- 4% permissible variation thereof). The product under consideration in the present sunset review is the same as has been held by the Designated Authority in the original investigation. Viscose Rayon Filament Yarn is a regenerated cellulosic yarn. Unlike synthetic yarns which are produced from petroleum products, Viscose Rayon Filament yarn is produced from natural renewable resources ie; wood pulp. It is 100% biodegradable and eco-friendly.
- ii. The product under consideration would remain the same as was defined in the course of original investigation.
- iii. Over the years there was presence of certain confusion in regard to the scope of VFY that was excluded from the scope of the investigation. The Custom Authorities accordingly issued a statement clarifying the definition of the excluded category of the subject good for the purpose of fair investigation.
- iv. Post Initiation of Anti-Dumping Duty, varied descriptions have been used and new descriptions have been invented, to evade Anti-Dumping Duty.
- v. Viscose Filament Yarn is classified under heading 5403.31, 5403.32, 5403.33, 5403.41 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.
- vi. Subject goods can be produced by three processes namely; Continuous Spun Yarn (CSY). Part Spun Yarn (PSY) and Spot Spun Yarn (SSY). Domestic Industries produce the subject good from all the three processes. However the subject good in the subject country is produced only through PSY and CSY process.
- vii. Bamboo fiber cannot be excluded from the current scope of the product under consideration as the current investigation is a review investigation and the same cannot be modified at this stage of the investigation. The party have also requested for exclusion of VFY below 75 deniers however the same cannot be considered for the above mentioned reasons and also because the party failed to provide any compelling evidence reasoning the removal of VFY below 75 deniers.
- viii. It was submitted that the Authority in the current investigation didn't modify the scope of the product. Rather through its notification No. 15/25/2014 dated 11<sup>th</sup> January, 2016 issued a clarification in regard to the excluded category of the product under consideration in response to the circumvention petition filed.
- ix. Interested party had claimed that un-dyed embroidery yarn cannot be used for any purpose for which the product under consideration is used. Such an allegation is factually incorrect and the same should be rejected.
- x. Other interested party had also alleged the inappropriateness in the PCN adopted in the current investigation. However, the same party have failed to provide any suggestion with regard to the kind of PCN that could be adopted.
- xi. The Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the original investigation, which is relied upon.

### **Submissions of the other interested parties**

11. Submissions made by other Interested parties are as follows:

- i. Undyed Embroidery yarn has been brought within the product scope in the current sunset review investigation but the same was not within the product scope in the original investigation as well as the first sunset review and hence should be excluded.
- ii. The Custom Notification No. 32/2016- Customs (Anti-Dumping Duty) dated 14.07.2016 issued by the Ministry of Finance suffers from non-application of mind and is without the Authority of the law or jurisdiction. The notification did not disclose appropriate reasons for expansion of the product scope and to include within its scope “undyed embroidery yarn.”

- iii. Embroidery yarn was consciously excluded from the purview of the original investigation and subsequent request for inclusions were specifically rejected in the mid term review as well as in the first sunset review investigation by the Designated Authority.
- iv. The embroidered yarn is not a like article to viscose filament yarn
- v. Classification of Product under consideration as per PCN proposed by the petitioner is not appropriate as there is no substantial difference in the product formed from different technologies.
- vi. SSY is a technology which is more advanced than PSY but less advanced than CSY and it's a similar technology to that of PSY. Thus, VFY produced through SSY is not different from VFY produced by PSY and CSY.
- vii. Need to exclude the VFY made of bamboo from the current scope of the product on the basis of different raw materials, different applications, catering to different markets, different Tax ID numbers and also but solely because both the products are not substitutable.
- viii. There is a need to exclude Viscose Filament yarn below 75 deniers from the scope of current investigation, thereby defining the scope of the product under consideration.
- ix. The petitioners did not furnish any evidence substantiating the evasion of anti-dumping duty as a result of wrong description of the imported product.
- x. The Designated Authority cannot re-examine or re-determine the scope of the product under consideration in a review investigation.
- xi. Authority need to clarify the types of embroidery yarn which continue to be excluded from the scope of Anti-Dumping Duty.

#### **Examination by the Authority**

12. The product under consideration in this investigation is Viscose Rayon Filament Yarn up to 150 deniers (and +-4% permissible variation thereof) including mono filament yarn of less than 67 decitex also known as viscose filament yarn or VFY, Rayon Filament Yarn, Art Silk Yarn, Cellulose Yarn or Rayon Yarn and includes all yarns made of 100% viscose yarns such as dyed yarn, flat yarn, microfilament micro yarn, twisted yarn (with the exclusion of embroidered yarn), doubled/ multiple ply yarn etc of VFY unless specifically excluded in this paragraph (also referred to as subject goods herein after). Further the PUC excludes embroidery yarn- this is clearly "dyed viscose rayon embroidered thread", sewing thread, fur yarn, fire retarded yarn, engineered yarn and anti-textured yarn.

13. The subject goods are classified under Customs sub-heads 54033100, 54033200, 54033300, 54034110, 54034120, 54034130, 54034140, 54034150, 54034160, 54034170, 54034180, and 54034190 though they have been reported to have been imported (in the investigations previously held on the subject) under other chapter heads as well (like chapter 55). Thus, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

14. At a later stage, the petitioners had approached the Authority with a circumvention petition as it was alleged that the exporters are trying to export the subject goods in the guise of embroidery yarn. To address the issue, the Authority had issued a letter, clarifying the scope of the Product under consideration in the current investigation to the Custom Authorities.

15. Further, a clarification was issued by the Custom Authorities on 14.07.2016 vide Notification No. 32/2016 which defined the scope of embroidery yarn. The legality of the notification was questioned by various parties and the same was brought for analysis in the High Court of Delhi. After detailed examination of the notification and the clarification given on the same, the court stated that:

*".....A. For exclusion of the product from imposition of anti-dumping duty, a yarn is considered as embroidered yarn/thread which is a finished ready to use product....."*

*B. Therefore, it would mean that by definition embroidered yarn is coloured and white is also a colour, which is a result of processing raw yarn...."*

*C. In other words irrespective of the colour, the product concerned must fall within the meaning of "embroidered yarn" as clarified vide Notification dated 14.07.2016....."*

16. Keeping the above view, the Authority concludes that Embroidery yarn is excluded from the current scope and is subsumed within the definition of excluded items detailed in the Initiation Notification of the current investigation.

17. The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that in the original and subsequent review investigations, as per Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules. Hence the question of exclusion of VFY made from Bamboo fiber and VFY below 75 deniers does not arise in the current review investigation.

18. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:



*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

19. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. The subject product produced by the domestic industry is comparable to the Product under consideration in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

20. Thus, the Authority holds that the subject product produced by the applicant domestic industry is like article to the Product under consideration exported from the subject country, in accordance with the AD Rules.

### **SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

#### **Submissions of the domestic industry**

21. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:

- i. The petition was filed by M/s. Kesoram Rayon, a unit of Cygnet Industries & M/s Indian Rayon, a unit of Grasim Industries; as the domestic producers of the product under consideration and supported by M/s. Century Rayon. There are no other producer of the subject good in India. These three are the sole producers of the subject good.
- ii. While the petition was filed, the domestic industry has no data in regard to the production and sales of the product under consideration in Century Rayon. Hence initially the standing was calculated based on the entirety of production of Century Rayon. At a later stage when the petitioner received the support letter stating Century Rayon's exact production and sales in respect of the product under consideration, an amended standing table was provided. However the same didn't affect the eligibility of the domestic Industry.
- iii. Production of petitioners constitutes a major proportion in Indian Production (both after including and excluding support by M/s Century Rayon) and therefore, the petitioner should be treated as "domestic industry" within the meaning of the Rules.
- iv. The petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and further, is not related to any exporter or producer of the subject goods in China or any importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).
- v. An interested party has raised suspicion in regard to the absence of major producer M/s Century Rayon from the scope of Domestic Industry however the question is irrelevant as the both M/s. Kesoram Rayon, a unit of Cygnet Industries & M/s Indian Rayon, a unit of Grasim Industries; is an eligible domestic Industry under the rules for the purpose of current investigation.

#### **Submissions of the other interested parties**

22. Submissions made by other interested parties are as follows:

- i. No information regarding the biggest constituent of domestic industry M/s Century Rayon has been provided.
- ii. Thus, for failure of including the major producer details in the petition, the investigation may be terminated.
- iii. Refusal to provide details of M/s Century Rayon would only imply that the Domestic Industry is picking and choosing the constituents of Domestic Industry to gain favorable outcomes.
- iv. The initiation notification referred applicant industry as M/s Kesoram Rayon and M/s Indian Rayon whereas submission from the applicant referred the applicants as M/s Cygnet Industries and M/s Indian Rayon.

#### **Examination by the Authority**

23. The application has been filed by M/s. Kesoram Rayon, a unit of Cygnet Industries & M/s Indian Rayon, a unit of Grasim Industries and is supported by M/s. Century Rayon.

24. The applicants constitutes 54% of the total domestic production; and, with support of M/s Century Rayon, the applicant constitutes 100% of the total Indian production, as seen from the table below. Further, the petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and, is not related to any exporter or producer of the subject goods in subject country or any importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).

**Indian Production**

SN	Particulars	Unit	Period			
			2013-14	2014-15	2015-16	POI
A	Petitioner Companies					
1.	Indian Rayon	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>		100	113	115	118
2.	Kesoram Rayon	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>		100	94	108	87
3.	Total of Petitioner companies	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>		100	108	113	110
4.	Supporter Company- Century Rayon	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>		100	103	114	119
5.	Total Indian Production	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>		100	105	114	114
6.	Share of Petitioner companies	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>		100	108	113	110
7.	Share of Supporter company	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>		100	103	114	119
8.	Share of Petitioning and supporter company	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>		100	105	114	114
			Share			
B	Petitioner Companies		2013-14	2014-15	2015-16	POI
1.	Indian Rayon		41%	44%	41%	42%
2.	Kesoram Rayon		15%	14%	15%	12%
3.	Total of Petitioner companies		56%	57%	56%	54%
4.	Supporter Company- Century Rayon		44%	43%	44%	46%
5.	Total Indian Production		100%	100%	100%	100%
6.	Share of Petitioner companies		56%	57%	56%	54%
7.	Share of Supporter company		44%	43%	44%	46%
8.	Share of Petitioning and supporter company		100%	100%	100%	100%

25. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the applicant satisfies the standing requirements and constitutes domestic industry under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

**ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY****Submissions of Domestic Industry**

26. Submissions made by the Domestic Industry are as follows:

- i. The petitioner has clearly notified that only such information has been claimed confidential which are permitted under the rules and the petitioners have provided detailed summary as to why the required information has been claimed confidential thereafter.
- ii. Interested party have raised allegations in regard to the authenticity of the non-confidential version of the application, however the parties have failed to substantiate such claims and are pure generic which shouldn't hold standing in the current investigation.

- iii. Excessive confidentiality has been claimed by the exporters in their Exporter's Questionnaire Response submissions and the response also lack various information which are discussed in the respective issues below.

#### **Submissions of other Interested Parties**

27. Submissions made by various interested parties/exporters/importers are as follows:
- The non-confidential version of the petition doesn't allow for a reasonable understanding of the allegations contained therein and it prevented interested parties to exercise their right to defend throughout the investigation.
  - Significant data provided in the petition is not properly indexed in the non-confidential version.

#### **Examination by the Authority**

28. The Authority made available non confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).

29. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-Dumping Rules provides as follows: -

*"Confidential information"*

*(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

30. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not provided to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

#### **ISSUES REGARDING INITIATION OF INVESTIGATION**

##### **Submissions of the Domestic Industry**

31. Submissions made by the Domestic Industry in this regard are as follows:
- It is submitted that the application was substantiated enough for the case to be initiated on the basis of the substantiated application.
  - It has provided detailed analysis in regard to the various economic parameters required for injury analysis and also on likelihood parameters.
  - Various interested parties have also highlighted that the anti-dumping duty has been in force for 10 years/11 years and that there exist no exceptional circumstance for continuation of the duty. On this note it is submitted that though *de jure* the injury has been in place for 11 years however *de facto* the same has been effective post change in form of the duty during the last sunset review. The same can be concluded from the improvement in the performance of domestic industry in last 5 years. Further in its submissions petitioners have highlighted various instances where the duty has been prolonged for more than 10 years and which prove time is never a consideration while deciding for extension of duty. It has also been submitted that the act of circumvention on behalf of the exporters is what acts as an exceptional circumstance in the current case and hence in all probability the imports would intensify causing injury to the domestic industry.

##### **Submissions of the Interested Party**

32. Submissions made by the interested party in this regard are as follows:
- Petition fails to meet the standards laid down in Rule-7 of the Rules and Trade Notice No 1/2013 dated December 09, 2013 issued by the Designated Authority.

- ii. Petitioners simply fail to demonstrate that imports from subject country have caused any injury to the Domestic Industry and hence the investigation was wrongly initiated.
- iii. Petition filed by the Domestic Industry does not contain information about various important parameters for the period of investigation. Absence of the same restricted the exporters from understanding the basis for initiation of the investigation.
- iv. The information provided by the Petitioner is manifestly insufficient to justify the initiation of an investigation under Rule-5(3) of the Rules.
- v. Indexed data on unit price, total costs, investments, employment and stocks are not explicitly provided and analyzed in the narrative of the petition, which lacks a meaningful analysis.
- vi. The Anti-Dumping Duty has been continuing for 10 years and there exist no special/exceptional circumstances for continuance of anti-dumping duty taking into current facts of the investigation.

#### **Examination by the Authority**

33. The Authority in its initiation notification has already noted that the current investigation is being initiated based on duly substantiated application filed in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules.

#### **MISCELLANEOUS ISSUES**

##### **Issues by other Interested parties**

34. The Authority had received submissions from various interested parties, a list of which is reproduced below:

- i. M/s Krunal Textiles,
- ii. M/s Guru Febrics,
- iii. M/s Hariom International,
- iv. M/s Shree Sahjanand Textiles,
- v. M/s Prakash textiles,
- vi. M/s Shiv s balvantraï rotriwala,
- vii. M/s Patel Pravinkumar Maganlal huf
- viii. M/s Ram Interprise,
- ix. M/s Shiv Textiles,
- x. M/s Denish Textiles,
- xi. M/s Mukund Textiles,
- xii. M/s Shree Jalaram Textiles,
- xiii. M/s Saurabh Textiles,
- xiv. M/s Liberty Trendz Limited,
- xv. M/s Guru Febrics,
- xvi. M/s Harsha Textiles,
- xvii. M/s Ranjit febrics,
- xviii. M/s Mukesh Balvantraï Rotriwala,
- xix. M/s Batsons Textiles,
- xx. M/s S.K. Weaving Pvt. Ltd.,
- xxi. M/s Ishwarkrupa Textiles,
- xxii. M/s Sonel Silk Corporation,
- xxiii. M/s Patel Dashrathlal Maganlal,
- xxiv. M/s Reaghan Fashion Pvt. Ltd.,
- xxv. M/s Patel Amratlal Maganlal Huf,
- xxvi. M/s Krishna Sales Corporation,
- xxvii. M/s Urjaa Exim Private Limited,
- xxviii. M/s Bittu Synthetics Pvt. Ltd.,

- xxix. M/s KTC Thread LLP,
- xxx. M/s Baijoo Fabrics,
- xxxi. M/s Rinkesh Textiles,
- xxxii. M/s Tejoday Dyeing & Printing Works,
- xxxiii. M/s Manohar Capital Market Ltd.,
- xxxiv. M/s J.M. Textiles,
- xxxv. M/s Shri Girnar Fabrics,
- xxxvi. M/s Himjyoti Industries,
- xxxvii. M/s SILK POLY FAB
- xxxviii. M/s Sachin Industrial Co.op Society Ltd.
- xxxix. Federation of Gujarat Weaver's Welfare Association.
- xl. M/s Suprabhat print pvt ltd
- xli. M/s Superb Threads

35. The submission made by the above mentioned parties are :

- i. Allegation of Injury or Likelihood of further Dumping and Injury is unsubstantiated.

#### **Examination of the Authority**

36. In response to the submissions received, the Authority had issued letters asking the above mentioned interested parties to provide a fully detailed importer questionnaire response and such other details which would be essential to substantiate their claim. However, none of the above parties have responded to the same, failing to substantiate their claims.

#### **Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin**

##### **Normal Value under the Rules:**

37. According to Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975, 'Normal Value' in relation to an article means: -

*comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

#### **Submissions of the Domestic industry**

38. The domestic industry inter alia submitted as follows:

- i. One of the provisions of Accession protocol has expired on 11<sup>th</sup> December, 2016. The Designated Authority should proceed with present investigation considering Chinese producers as producers operating in non-market economy conditions.
- ii. The investigation period considered by the Authority in the present case is April 2016 to March 2017 (12 months). The injury investigation period has been considered as the period 2013-14, 2014-15, 2015-16 and POI.
- iii. The purpose of fixing of POI is to consider a period when the existence of dumping causing injury is claimed and established. The date of determination is not relevant to the moot question of dumping causing injury to the domestic industry. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone should be considered relevant, appropriate and necessary for the purpose.

- iv. The Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies for the reason that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces. Para 8 to Annexure-I specifies the parameters which should be considered for grant of market economy status. This also implies that unless these conditions are not fulfilled/ satisfied, the Chinese costs and prices cannot be adopted.
- v. Since Chinese companies have been denied market economy status for the reasons mentioned in Para 8 of Annexure-I till December, 2016, petitioner submits that the Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies till such time the investigation period includes the period specified in Accession Treaty protocol.
- vi. In the context of rule 2(b), it is well established legal position that the imports by a domestic producer or its relationship with an exporter or importer are examined with reference to the investigation period. If POI alone is relevant for standing purposes, POI alone should be relevant for normal value determination.
- vii. Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
- viii. Normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not available. The petitioner has claimed consideration of normal value on the basis of cost of production in India duly adjusted.
- ix. The dumping margin from China is not only significant, but also substantial, thus establishing existence of significant dumping of the product under consideration in India. The import volume of China has remained significant throughout the present injury period, despite anti dumping duty in force.
- x. Considering the production capacities available with Chinese producers and their high export orientation, dumping would continue and even intensify in the event of cessation of anti dumping duty.
- xi. An interested party raised an allegation that the petitioners have failed to provide the methodology used for calculation of normal value however the same is not true as the details have been provided in the application.

#### **Submissions of the interested parties**

39. Interested parties raised the following issues:
  - i. All exporters should be granted Market Economy status after 11<sup>th</sup> December, 2016. Issuance of market economy questionnaire is discriminatory and in violation of obligations on the WTO members under the protocol of China's accession to WTO.
  - ii. India must fulfil its obligations under relevant agreements to recognise China's full market economy status and amending relevant domestic regulations. Further, the "surrogate country" approach in anti-dumping investigations against China should be stopped.
  - iii. The petitioners have not disclosed the methodology adopted for calculation of normal value and export price.

#### **Examination by the Authority**

40. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

(c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

(d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

41. Article 15 implies that provisions of one of the subparagraph shall expire 15 years from date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired on 11<sup>th</sup> Dec., 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is April, 2016 to March, 2017. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the major period of investigation, the Authority shall use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

42. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

#### **Examination of Market economy claims**

43. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Anti-Dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provides information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:

- i. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- ii. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- iii. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- iv. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

44. None of the exporter/producers have responded and filed the supplementary questionnaire response. Hence, the Authority is constrained in determining sufficiency of MET claims. Thus, arguments by the China Chamber of International Commerce and China Chemical Fibers Association are declined. In view of the above position the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and in accordance with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

#### **Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR**

45. The Authority has determined normal value having regard to para-7 of Annexure-I for the purpose of present investigation. The normal value for the subject products imported from China PR into India has been constructed considering optimum consumption norms of the domestic industry for major raw materials, cost of raw materials, is as per international prices, conversion cost, interest, SGA etc. at the levels allowed for the domestic industry. 5% of cost of sales excluding interest has been allowed towards reasonable profit.

#### **Determination of Export Price**

#### **Submissions of the Domestic Industry**

46. The various submissions made by the Domestic Industry are as follows:

- i. With reference to M/s Xinxiang Chemical Fibre Co. Ltd it has been submitted by the petitioner that the exporter in their response to question A.5 has stated that there is no related and subsidiary company involved in the production or sales of the product concerned. However, M/s Xinxiang Bailu Investment Co. Ltd ("Bailu") - holding company of Xinxiang, is involved with the export of the product concerned.

- ii. It is noted the exporter has failed to provide relevant information in their exporter questionnaire. Failure to do the same affects the methodology to ascertain the net export price of the group as a whole. In accordance with the same, the Authority may find it appropriate to reject the EQR filed by M/s Xinxiang Chemical Fibre Co.

#### **Submissions of the interested party**

- i. The petitioner has failed to disclose the methodology adopted for determination of export price.
- ii. Exporters from China cooperated and hence export price and Dumping Margin should be determined on the information provided by these exporters.

#### **Examination by the Authority**

47. The Authority notes that the following Chinese producers/ exporters have filed exporter questionnaire response in the present investigation:

- a. Jilin Chemical Fiber Stock Co. Ltd.
- b. Jilin Enka Viscose Co. Ltd.
- c. Yibin Heist Fibre Co. Ltd.
- d. Xinxiang Chemical Fibre Co. Ltd.(XCF)

48. With reference to M/s Xinxiang Chemical Fibre Co. Ltd, it has been submitted by the petitioner that the exporter in their response to question A.5 has stated that there is no related and subsidiary company involved in the production or sales of the product concerned. However, M/s Xinxiang Bailu Investment Co. Ltd ("Bailu") - holding company of Xinxiang, is involved with the export of the product concerned.

49. The exporter mentioned that among Bailu's subsidiary, only XCF produces the viscose filament yarn and exports the viscose filament yarn to India. They have mentioned that Bailu itself does not produce or sell the viscose filament yarn. The exporter has mentioned that they shall be submitting the profit statements of Bailu for year 2016 and Bailu's trial balance for the Accounts of revenue which shall show that Bailu has no revenue of viscose filament yarn. However, it is noted the exporter has not submitted the relevant documents with certified translations of the same, in this regard. Failure to do the same affects the methodology to ascertain the net export price of the group as a whole. In accordance with the same, the Authority is constrained to determine individual dumping margin of the same.

50. After examination of the responses, the DGCI&S data has been examined. The data submitted by the exporters were verified and the appendix wise response to the exporter's questionnaire was taken up for examination.

51. The Authority has determined the export price for other (non-cooperating) producers/exporters of China PR on the basis of the DGCI&S transaction wise data. Accordingly, the weighted average net export price at ex-factory level, in respect of all exporters from China PR has been determined after making due adjustments for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Bank Charges, Port Expenses and Inland Freight Charges on the basis of best available information and the same has been mentioned in the dumping margin table.

#### **Determination of Dumping Margin**

52. The export price to India (net of all the adjustments accepted by the Authority) has been compared with the normal value to determine dumping margin. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from subject country has been determined as provided in the table below:

#### **Dumping Margin**

53. The dumping margin for subject goods has been determined by comparing constructed normal value and net export price. The table below shows the calculated dumping margin for producers/exporters from subject country:

Sr. No	Producer/Exporter	Normal Value (USD/MT)	Net Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin %	Range %
1.	Xinxiang Chemical Fibre Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA
2.	M/s Yibin Hiest Fibre Co. Ltd.	***	***	***	***	1-10
3.	Jilin Chemical Fibre Stock Co. Ltd.	***	***	***	***	(1-10)



4.	Jinlin Enka Viscose Co. Ltd.	***	***	***	***	(1-10)
5.	Residual Category	***	***	***	***	20-30

### METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

#### INJURY AND CAUSAL LINK

##### Submissions of the Domestic industry

54. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:

- i. The demand/apparent consumption of the subject goods have increased over the injury period including the POI. Imports from subject country have remained significant despite anti-dumping duty, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India.
- ii. Landed price of imports (after including basic customs duties) is significantly below the selling prices of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting. Under the circumstances, should the present anti-dumping duty cease, the imports would further undercut the prices of the domestic industry, which would prevent price increases to a significant degree.
- iii. The landed price of imports from China is materially below the cost of the domestic industry.
- iv. The share of imports from subject country in total imports has increased.
- v. The imports are supposed to be suppressing and depressing the prices of domestic Industry in case of cessation of Anti Dumping Duty.
- vi. Market share of subject imports has declined as a result of anti-dumping duty being in force. However, the market share of subject imports is still very significant.
- vii. The domestic industry enhanced its capacity during the injury period. One petitioner has added its capacity for CSY and another company has added capacity for SSY. The enhancement in capacity was fully justified by the present and potential demand for the product in the Country. Domestic sales volume has also increased over the injury period.
- viii. The DI has analyzed the parameters based on different technologies being adopted by the producers and exporters. It is seen that taken in regard the technology of SSY, the Domestic Industry seems to be earning profit; excluding the same the Domestic Industry is suffering losses irrespective of Anti-Dumping Duty being in force.
- ix. However, given the level of price undercutting, it is evident that the demand for the imported product would substantially increase in the event of cessation of anti dumping duties. This would directly imply decline in the demand of the domestic product, which is likely to result in decline in production of the domestic industry.
- x. Performance of the domestic industry in terms of price parameters such as profits, cash profits and return on capital employed has also shown improvement in the POI.
- xi. Presence of significant dumped imports would result in continued dumping leading to recurrence of injury in the absence of anti-dumping duty.
- xii. Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant.
- xiii. Given the price difference between the domestic and imported product, should the present anti-dumping duty be allowed to cease at this stage, petitioners submit that the domestic industry would immediately start suffering financial losses.
- xiv. Considering the present level of antidumping duty, even if the lowest amount of antidumping duty is considered, the landed price of imports shall decline by more than Rs. 20 per kg. The profits earned by the domestic industry during the present POI are below this level. This itself shows that the domestic industry shall suffer financial losses in the event of cessation of antidumping duty.
- xv. Considering the capacities with the exporters in the subject country and their export orientation, there is likelihood of intensified imports in case existing anti-dumping duties is allowed to cease.
- xvi. Resultantly, the domestic industry is likely to suffer injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xvii. The anti-dumping duty is required to be continued. The form of measure is required to be kept as fixed quantum in terms of US\$.

**Submissions of other interested parties**

55. In the current investigation one of the party had separately filed injury submission and the issues raised therein are:

- i. Performance of the domestic industry has been stable or improved in respect of various economic parameters;
- ii. Allegation of Injury or Likelihood of further Dumping and Injury is unsubstantiated.
- iii. Any injury allegedly suffered by the domestic industry has been caused by factors other than imports from the China PR.

56. Further after the public hearing interested parties through their rejoinder and written submissions raised the following issues:

- i. Petitioners simply fail to demonstrate that imports from subject country has caused any injury to the Domestic Industry.
- ii. There is negative price undercutting and negative injury margin in the present circumstances.
- iii. The fine deniers and super fine deniers are produced via SSY technology in India. Where the SSY product is included, the injury economic parameters provided in Proforma IV-A show the domestic industry is in good health. Therefore, it is important to note that the fine deniers and super fine deniers produced by the domestic industry are competitive with those imported from China.
- iv. The consumption on the present Indian market is gradually shifting from coarse deniers to fine deniers.
- v. Performance of Domestic Industry has improved in respect of various economic parameters and domestic industry did not suffer any volume impact as a result of imports from China.
- vi. It is not permitted to exclude sub-set of like product from injury analysis of domestic industry for the sole reason that they are being produced through different technologies.
- vii. The blind protection provided by GOI will lead to monopolization and adversely impact public interest.
- viii. Most of the applicant company haven't upgraded their technology over the years.
- ix. Domestic Industry's is incapable of supplying international standard quality of yarns.

**Examination by the Authority**

57. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Antidumping Rules and considering the submissions made by the other interested parties appropriately.

58. As regards the submissions of absence of injury, the injury analysis carried out hereunder is self-explanatory to establish if dumping has caused injury to the domestic industry or not.

59. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as below:

60. The Authority has examined injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

61. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of Anti-dumping rules states as under:-

*(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.*

62. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration; while some may show improvement. The Designated Authority considers all injury parameters and thereafter concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments in the submissions.

**Volume Effect of dumped imports and impact on domestic industry****Demand and Market Share**

63. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

**Demand and Market Share**

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
<b>Demand</b>					
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Sales of Supporter company	MT	***	***	***	***
Imports from China	MT	18,781	16,094	9,862	10,261
Imports from Other Countries	MT	842	245	11	26
<b>Total Demand</b>	<b>MT</b>	<b>47,169</b>	<b>45,429</b>	<b>44,113</b>	<b>41,963</b>
<b>Market Share in Demand</b>					
Share of Domestic Industry	%	31.64%	35.50%	43.24%	40.18%
Share of Supporter Company	%	26.76%	28.53%	34.38%	35.30%
Share of China PR	%	39.82%	35.43%	22.36%	24.45%
Share of Other Countries	%	1.79%	0.54%	0.02%	0.06%
Total	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

64. The Authority notes that the demand for the product under consideration has decreased in the POI as compared to base year as well as previous year.

65. It is noted that the market share of the domestic industry, has increased; whereas the market share of the subject country imports has declined over the injury period, although, still significant.

66. The market share of the other countries imports has declined.

**Import volumes and share of subject country**

67. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject country have been analysed as under:

**Imports and Market Share**

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	128	113
Sales of Supporter Company	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	120	117
Imports of Subject Countries- China	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	53	55
Imports of Other Countries	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	29	1	3
Total Imports	MT	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	83	50	52
Total Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	94	89
Total Indian Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	114	114
Subject Country Imports in relation to :-					
Total Imports	%	96%	99%	100%	100%
Production	%	65%	53%	30%	31%
Consumption	%	40%	35%	22%	24%

68. The market share of subject imports in relation to production and consumption in India has significantly decreased over the injury period; reduced to almost half of the share in POI as compared to base year.

69. There has been a decline in the consumption of the subject goods in India.

#### **Price Effect of dumped imports and impact on domestic industry**

##### **Price Undercutting**

70. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

71. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The price of the domestic industry was determined at the ex-factory level. The Authority has compared landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the subject goods.

#### **Price Undercutting**

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Net Sales Realisation	Rs/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	107	107	114
<b>CHINA</b>					
Landed Price without ADD	Rs/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	97	103	102
Price undercutting	Rs/KG	***	***	***	***
Price undercutting %	%	-11.29%	-2.12%	-8.01%	-0.87%
Landed Price with ADD	Rs/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	97	103	102
Price undercutting	Rs/KG	***	***	***	***
Price undercutting %	%	-15.55%	-6.82%	-12.43%	-5.63%

72. The net sales realization has increased by 14% in POI as compared to base year.

73. The landed price has also increased marginally over the base year.

74. There appears nil price undercutting

**Price Underselling**

75. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject countries. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject country. Comparison of the NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

**Price Underselling**

Particulars	Unit	POI
		China PR
Non-Injurious Price	Rs./MT	***
Landed Value	Rs./MT	***
Price Underselling	Rs./MT	***
Price Underselling - %	%	***
Price Underselling - % Range	% Range	(0-10)

76. It is noted from the above table that there is negative price underselling on account of imports of the subject goods from China

**Price suppression and depression effects of the dumped imports**

77. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

**Price Suppression/ Depression**

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	103	104	110
Net Sales Realisation	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	107	107	114
Landed Price without ADD	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	97	103	102
Landed Price with ADD	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	97	103	102

78. From the above table, it is clear that the landed value of imports from the subject country have shown an upward trend in injury period as compared to the previous years.

79. The cost of production has increased by 10% over the base year and net sales realization increased by 14%.

**Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry**

80. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

81. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry are analyzed herein below:

**Capacity, Production, and Capacity Utilization**

82. The performance of the domestic industry with regard to production, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	100	101	107
Plant Production	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	102	106	103
Production-PUC	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	108	113	110
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	102	105	96

83. It can be seen that the production of the Domestic Industry has increased throughout the injury period.

84. The capacity utilization of the Domestic Industry also followed the same trend as that of production.

**Sales Volumes**

85. The sales parameters both in terms of volume and prices are demonstrated below :

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	108	128	113
Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	116	137	129
Selling Price- Domestic	Rs./KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	107	107	114
Export Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	131	171	114
Export Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	112	143	103

Selling Price- Export	Rs./KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	85	84	90
Total Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	109	129	113
Total Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	115	137	128

86. It is noted that the sales volume of the Domestic Industry has increased gradually throughout the injury period.

87. The sales price has also been steady and increasing gradually throughout the injury period.

#### **Market Share**

88. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

#### **Market share in Demand**

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
<b>Market Share in Demand</b>					
Share of Domestic Industry	%	31.64%	35.50%	43.24%	40.18%
Share of Supporter Company	%	26.76%	28.53%	34.38%	35.30%
Share of China PR	%	39.82%	35.43%	22.36%	24.45%
Share of Other Countries	%	1.79%	0.54%	0.02%	0.06%
Total	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

89. It is noted that the market share of the domestic industry, has increased; whereas the market share of the subject country has decreased even in the presence of Anti-Dumping Duty.

90. The market share of imports from other countries have decreased.

#### **Inventories**

91. The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table :

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	188	148	83
Inventory Per Day	MT/Days	3	5	4	2
<i>Trend</i>	Indexed	100	188	148	83

92. It is noted from the above that the inventory per day is not very high and the same has been gradually decreasing further over the injury period.

#### **Profits, return on investment and cash flow**

93. The profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analyzed as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Cost of Sales	Rs/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	103	104	110
Selling Price	Rs/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	107	107	114
Profit / Loss	Rs/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	507	446	534
Profit / Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	548	570	603
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	187	193	223
Profit before Interest & Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	197	195	208
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	187	175	130

94. The profitability parameters of Domestic Industry improved over the injury period.

95. Similarly, profit before interest, cash profit and return on investment have shown a positive trend.

#### **Employment, Wages and Productivity**

96. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	102	102	109
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	107	121	125
Productivity Per Employee	MT/Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	105	111	101
Productivity Per Day	MT/Days	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	108	113	

97. The Authority notes that the figures relating to the productivity of the Domestic Industry has consistently improved throughout the injury period.

#### **Growth**

Particulars	YOY	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Production	%	-	7.69	5.36	(3.37)
Domestic Sales Volume	%	-	8.09	18.27	(11.60)
Cost of Sales	%	-	3.12	0.82	5.68
Selling Price	%	-	6.95	0.24	6.23



Profit/ Loss per unit	%	-	406.91	(12.02)	19.69
-----------------------	---	---	--------	---------	-------

98. The domestic industry has contended that with increase in demand, the domestic industry had expected growth in profits, comfortable cash flow and increase in return on investments. However, the domestic industry was not able to achieve the same to the desired levels due to the presence of the dumped imports from subject countries.

99. The table shows that the growth of domestic industry has been positive for most of the parameters with a dip in production and domestic sales volume in POI.

#### **Magnitude of Dumping**

100. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The analysis shows that the dumping margin determined against the subject country is above *de minimis*.

#### **Ability to raise Capital Investment**

101. There is no verifiable information presented by the Domestic Industry and neither available on records that can imply that future investment in the sector can be marred by the presence of dumped imports from subject country.

102. Ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector may not be affected due to the dumped imports from the subject countries.

#### **Conclusion on Injury**

103. Having regard to the information on record and after examination of the performance of the Domestic Industry, the Authority notes that the dumped imports of the subject goods from subject country has decreased in absolute terms. Significant decrease in imports is observed in relation to production and consumption of the subject goods in India.

104. The examination indicates that there is a marginal decrease in demand in India for the subject goods. It is also noted that the landed value of subject goods from subject countries are higher than the sales realization of the domestic industry. The domestic industry has been able to increase its prices by 14% where cost of sales has increased by 10% over the injury period, as seen from table at para 77.

#### **MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**

105. The determined non-injurious price of the subject goods produced by the Domestic Industry has been compared with the landed value of the exports from subject countries for determination of injury margin during POI as under:-

Sr. No	Producer/Exporter	NIP (USD/MT)	Landed Value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin %	Range %
1.	Xinaxiang Chemical Fibre Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA
2.	M/s Yibin Hiest Fibre Co. Ltd.	***	***	***	***	5-15
3.	Jilin Chemical Fibre Stock Co. Ltd.	***	***	***	***	(0-10)
4.	Jilin Enka Viscose Co. Ltd.	***	***	***	***	(0-10)
5.	Residual category	***	***	***	***	25-35

#### **LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

106. The Authority observed that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if the anti-dumping duties were to be allowed to expire even if there is no current injury.

#### **Submissions made by the Domestic Industry**

107. The domestic industry submitted as under in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- Significant dumping margin during POI establishes that dumping is likely to continue and intensify in the event of cessation of present anti dumping duty. Dumping existed during the entire injury period. Also, high dumping margins existed during the previous anti dumping investigations. This clearly leads to a conclusion that in case of

cessation of antidumping duty, there is every likelihood of injury to the Domestic Industry.

- ii. The return on investment and cash profit would be significantly negative in the event of cessation of anti dumping duty.
- iii. The import prices are materially below the selling price of the domestic industry. The consumers would therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product. In case of cessation of anti-dumping duty, the domestic industry shall have to reduce their selling price to compete with dumped imports, forcing them to sell even below the cost of sales, leading to severe price injury.
- iv. Dumping Margin, Injury margin and price undercutting in respect of major exporter to India is significantly higher as compared to other whose volumes are lower. Collective margins in respect of exports to various third countries are significant and positive.
- v. The Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of low priced imports from the subject country in the market shall definitely cause an adverse impact on the domestic industry. So dumping and consequent injury to the domestic industry is likely to continue/increase in the event of cessation of anti-dumping duty.
- vi. The original and all subsequent investigations established existence of significant dumping. The dumping margin in the current period is also significant. The producers are likely to intensify dumping and cause injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.
- vii. Volumes of imports have remained significant even after Anti-Dumping Duty being in force. Further considering the existing Chinese capacities and their expansion and their act of circumvention shows that the Chinese producers are capable of taking away the entire Indian demand for the Product under consideration.
- viii. The act of circumvention clearly shows the likely behavior of producers from subject country. It establishes the dire need of the producers in subject country to dump subject goods owing to the huge surplus capacity available with them.
- ix. Excess capacities with the producers would be used to further export and dump their produce in India.
- x. CCF group Annual report has stated that closure of various plants of the subject good are mere speculations and that major producers are in the process of expanding their capacities.
- xi. There are significant exports of the product under consideration from China to third countries. The prices of the product to these countries are significantly lower and cessation of ADD therefore shall lead to diversion of these low priced exports to India.
- xii. The present status of the domestic industry is fragile and in the event of expiry of duty the domestic industry is likely to suffer losses and slip back to the status that was prevailing at the time of original investigation.
- xiii. The current volume per se is sufficient to establish likelihood of dumping & injury hence there is definitive likelihood of intensified imports in the event of expiry of existing anti-dumping duty.
- xiv. There is a need to determine injury margin in individual export transactions and accordingly consider those transactions where injury margin and price undercutting are positive.
- xv. Allegations by exporters that India is not a major market for VFY exporters are mere false allegations and the same can be contradicted from the information provided in the CCF's group report. The report clearly highlight that India is among the top 4 (four) markets where exporters sell their produce irrespective of Anti-Dumping Duty being in force.

**Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties**

108. The submission made by various interested parties are:
  - i. Allegation of Injury or Likelihood of further Dumping and Injury is unsubstantiated.
  - ii. Production capacity of subject good in China will not significantly increase in the future owing to environmental protection concerns and increase in remuneration of workers and need for huge capital investment.
  - iii. China's production capacity of the product under consideration in 2015 is lower than that in 2010, which is mainly due to the successive shutdown of various production plants of VFY.
  - iv. Exports to India are decreasing, and India is no longer the increasing market for Chinese producers and/or exporters.

- v. India is not the major target market of the viscose filament yarn originating in China.
- vi. The consumption on the present Indian market is gradually shifting from coarse deniers to fine deniers.
- vii. The capacity and the technology of the domestic industry cannot meet the demand of Indian market.
- viii. No other country has ever implemented anti-dumping, countervailing and safeguard measures concerning the product concerned from China PR.
- ix. No assessment of likelihood of injury can be made without considering the information of the biggest producer of the subject product.
- x. There is no likelihood of continuation of injury in the current investigation owing to the improvements in various parameters of the Domestic Industry.
- xi. None of the parameters based on which duty was continued in the previous SSR is present in this review.
- xii. Domestic Industry has not claimed likelihood of injury and dumping in the period of investigation i.e., April 2016 to March 2017.
- xiii. Claim of Domestic Industry that China is exporting to other countries at cheaper prices hold no good as combined analysis will lead to absurd results.
- xiv. CCF report is showing that the exporters are just increasing their exports but doesn't show expansion and that fact that other producers are closing. It also shows that there is not much new addition to the existing capacity

### **Examination of Authority**

109. The Authority has examined the contention of the Domestic Industry and other interested parties to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury with specific reference to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules. Clause (vii) of Annexure II to the rules read with Nirma Ltd. Vs Union of India 2017(346) E.L.T 328 (Guj) decided on 13/12/2016.

#### **(a) significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation**

110. It is noted that the Authority has not received post POI information from the domestic industry or the exporters and other interested parties.

111. Further, the exporters have not submitted transaction-wise third country export data in the form and manner of part II of the exporter's questionnaire.

112. This has constrained the Authority to establish continuation of dumping of subject goods from subject country post POI, with corroborating statistical evidence.

113. Further, the contention that domestic industry will continue to suffer injury because of continued dumped imports from subject country, cannot be established in the instant case for the following reason: (a) In the present case, the domestic industry is not suffering injury on any of the major economic parameters during the period of investigation, as seen from the preceding paragraphs on injury analysis and examination of major economic parameters (b) no verifiable documents submitted to claim injury in the post POI period.

#### **(b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports**

114. This parameter for ascertaining the threat of material injury requires evaluation of existing surplus capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market. Domestic industry has claimed that the producers in subject countries are already faced with significant capacities.

115. Further, these producers are exporting the product to a large number of countries, a very significant proportion of which is being exported at a price below the prices in respect of Pakistan, thus showing likelihood of diversion of these exports to India in the event of withdrawal of Anti-Dumping duty. This argument could not be justified when corroborated with the demand and consumption of the subject good in India. It is pertinent to note that the demand and consumption of the subject goods have not increased throughout the injury period. On the contrary, the demand and consumption study done in preceding paragraphs have shown a declining trend.

116. None of the interested parties have provided any verifiable evidence and information with regard to existing surplus capacities, and consequent likelihood /possibility of increased dumped exports to Indian market.

**(c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports**

117. At the current landed price in India, there is no price undercutting throughout the injury period or during the POI in case of the subject goods from the subject country.

**(d) inventories of the article being investigated**

118. The facts available on records do not contain any dependable evidence on inventories of the article being investigated.

**(e) Circumvention of subject good by the producers from the subject country.**

119. The exporter has earlier been alleged to have circumvented the subject good to India in the name of “embroidery yarn.” Further, it has been alleged that evasion of duty continues in spite of clarifications. It is noted that evasion of duty is a separate investigation that may be addressed at the appropriate forum. The alleged act of circumvention cannot clearly establish an intention to dump subject goods in India.

**OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK**

120. Under Section 9A(5), the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports of the product under consideration during the review investigation period or not.

121. It was examined whether other parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It is noted as follows:

**(a) Volume and prices of imports from third countries**

122. The imports of the subject goods from countries other than the subject countries are not significant as revealed by the transaction-wise data from DGC&IS. Further, a decreasing pattern is seen throughout the injury period. In fact, the share of other country imports is negligible.

**(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.**

123. There has been a marginal decrease in demand of the product concerned throughout the injury period.

**(c) Developments in technology:**

124. Technology for production of the product concerned has not undergone any change.

**(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

125. There is no trade restrictive practice, which could have affected the Domestic Industry. The raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country.

**(e) Export performance of the domestic industry**

126. The injury analysis has been done by the Authority taking into consideration their domestic operations only. Therefore, performance in the export market has not affected the present injury analysis.

**(f) Productivity of the Domestic Industry**

127. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee as well as production per day has increased over the period.

128. The essential facts of the investigation, as gathered, analyzed and established by the Designated Authority during the course of the investigations on the basis of information received from various sources were disclosed to the interested parties in order to enable them to offer their comments on these facts as stated by the Designated Authority.

**POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY/ INTERESTED PARTIES**

**Submissions made by Domestic Industry**

129. The submissions made by the domestic industry are summarized as under :

- i. Petitioners are unable to understand whether PCN wise analysis was carried out to determine the normal value, export price, dumping margin, price undercutting and injury margin.
- ii. Authority failed to consider the correlation between increase in imports in the POI from the preceding years and its impact on the performance of the Domestic Industry.
- iii. Analysis of the Authority regarding performance of Domestic Industry is inappropriate and insufficient and the same needs more objective examination.
- iv. The Authority appears to have determined price undercutting without considered the PCN. If the same would have been considered it, would be seen that there is positive price undercutting in respect of those type of subject goods which are exported in large volumes.
- v. Determination of price underselling is also not appropriate as PCN wise analysis hasn't been considered for determination of the same.
- vi. Relevant submissions made by the petitioners may be examined in respect to considering individual export transactions and segregating the same into positive and negative while determining price undercutting and injury margin.
- vii. The Authority determined NIP and injury margin and this is against the decision of the High court in the matter of Nirma Ltd. vs. Designated Authority.
- viii. The petitioners confirm to the Product under consideration proposed by the Authority
- ix. No clarification provided by exporters in regard to the scope of Product under consideration.
- x. None of the exporters have provided transaction wise details of their global exports as the same is required to determine (a) dumping in third countries (b) price attractiveness of Indian market viz a viz other markets (c) behavior of the exporters.
- xi. Avoided providing any information with regard to the incentives received by them which are one of the reasons for their export orientation.
- xii. As no information provided, the Designated Authority is required to draw adverse inference in terms of Rule 6(8) of the Rules.
- xiii. The critical submissions made by Domestic Industry in reference to Injury and casual link have been completely ignored and hence inappropriate determination.
- xiv. The Authority has noted that the Domestic Industry has not grown to the extent it was expected to grow and this is owing to the imports from subject country.
- xv. Performance of the Domestic Industry is fragile and would suffer significant losses should the anti-dumping duty be allowed to cease.
- xvi. If the Domestic Industry holds its current prices, then in the event of cessation of duty the Domestic Industry will lose sales volume affecting the profitability and growth of the Domestic Industry.
- xvii. Considering Chinese capacities and their current expansion, and the nature/behavior of the exporters to dump goods even by circumventing anti-dumping duty, it is evident that the Chinese producers are capable of taking away entire Indian demand for the product under consideration.
- xviii. Observation of Authority in para 113 is inappropriate as it lacks objective analysis. Further good performance of the Domestic Industry doesn't mean there is absence of likelihood. Rather a mere increase in imports in the POI has adversely affected the sales volume of the Domestic Industry thus showing likelihood.
- xix. The Authority chose to ignore the concerns made by Domestic Industry in regard to expansion of Chinese exporters which was clear from CCF report so provided that the industry is growing and shows in all likelihood the exporters would dump the subject good into India.
- xx. Mere act of circumvention shows the keen interest of the exporters to dump the subject good into India.

- xxi. Authority failed to consider the relevant issues raised by Domestic Industry in the issues related to likelihood of dumping and injury.
- xxii. The original and all subsequent investigations established existence of significant dumping. The dumping margin in the current period is also significant. The producers are likely to intensify dumping and cause injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xxiii. Volumes of imports have remained significant even after Anti-Dumping Duty being in force. Further considering the existing Chinese capacities and their expansion and their act of circumvention shows that the Chinese producers are capable of taking away the entire Indian demand for the Product under consideration.
- xxiv. The act of circumvention clearly shows the likely behavior of producers from subject country. It establishes the dire need of the producers in subject country to dump subject goods owing to the huge surplus capacity available with them.
- xxv. Excess capacities with the producers would be used to further export and dump their produce in India.
- xxvi. CCF group Annual report has stated that closure of various plants of the subject good are mere speculations and that major producers are in the process of expanding their capacities.
- xxvii. There are significant exports of the product under consideration from China to third countries. The prices of the product to these countries are significantly lower and cessation of ADD therefore shall lead to diversion of these low priced exports to India.
- xxviii. Dumping margin and injury margin in terms of coarser yarn is positive in comparison to fine and super finer deniers and such a situation shows that export price differs significantly in respect of different products.
- xxix. The price undercutting and injury margin should be determined after excluding transactions having negative margins. This argument is without prejudice to Domestic Industry's submission that injury margin shouldn't be determined in the current investigation.
- xxx. The Designated Authority found that there is an improvement in the performance of domestic industry. Yet, Authority has proceeded to determine NIP, and injury margin, which are of no relevance for a likelihood analysis.
- xxxi. Mere improvement on account of duties, is not an indicator as to the state of affairs, once the duties are no longer in force.
- xxxii. Data provided by Domestic Industry would show that exports made to Pakistan are significant and there are complete chances of diversion of these exports to India.
- xxxiii. The petitioners have provided relevant information in regard to existing surplus capacities in China.
- xxxiv. Parameters of threat of injury cannot be applied in cases where Anti-Dumping Duty is in place.
- xxxv. Designated Authority has equated "likely to recur injury" with "threat of injury."
- xxxvi. While examining imports in relation to consumption, the disclosure statement does not consider that imports in relation to consumption declined between 2013-14, 2014-15 and 2015-16. However, there has been increase in imports in relation to consumption in the POI.
- xxxvii. The price undercutting and price underselling is significantly high in respect of coarser yarn and negative in case of fine and super fine yarns.
- xxxviii. The price undercutting and price underselling is negative in case of fine and super fine yarns for the reasons that (a) Authority has changed NIP determination methodology on its own and (b) even when unit of measurement is weight, the product is consumed in length.
- xxxix. The DA never called upon the domestic industry to justify the change in methodology adopted by the petitioners.
- xl. As per Para 77, 78 and 79 whereas cost of production increased by 10%, the import prices increased by 2%. Hence, Chinese produces did not increase their prices in proportion to increase in the costs.
- xli. The domestic industry has not claimed continued injury from dumped imports as rightly observed by the Authority in para 113.

- xlii. Likelihood of recurrence of injury does not imply material injury in post POI and therefore reliance solely on post POI to determine likelihood or recurrence of injury will not be appropriate.
- xlili. Further since the Anti-Dumping Duty is still in force post POI, the post POI data may not show likelihood of recurrence of injury.
- xliv. Since exporters have not cooperated with the authority with POI transactions wise data and other information, the authority should draw adverse inference against the exporters instead of drawing adverse inference against the domestic industry.
- xliv. Since Cygnet Industries was mentioned as petitioning company in initiation notification, it's not possible for the Authority to mention in para 130 that it wasn't aware of the fact.
- xlvi. No communication from the Directorate seeking any information on account of the details of the petitioning companies.
- xlvi. The capital employed determined in case of one of the petitioner companies is not in accordance with the information filed, nor is it in accordance with the facts of the case on record of the Designated Authority.

#### **Submissions made by exporters and other interested parties**

130. The submissions of the domestic industry are as under :

- i. The exporter claimed that Bailu itself does not produce or sell the viscose filament yarn. From the Profit Statements of Bailu for Year 2016, Bailu's total operating revenue for 2016 is only CNY 14,175,120.69, which is such a small amount and cannot be the revenue for a company producing viscose filament yarn. Bailu's main business revenue consists of revenue from sales of water, steam, electricity, equipment, equipment accessories, and revenue from labour service and leasing. Thus, Bailu itself does not produce or sell the viscose filament yarn, only XCF produces the VFY and export the same to India.
- ii. The exporter claimed that the imports from subject country are not causing injury to the Domestic Industry.
- iii. The Authority is requested to kindly correct the name of the cooperating producer / exporter to M/s Yibin Hiest Fibre Co. Ltd. in place of Yibin Heist Fibre Limited Corporation in the final findings.
- iv. At the outset, it is submitted that the Designated Authority in the instant disclosure statement has allowed excessive confidentiality without the Domestic Industry advancing any proper justification. Further, why such confidentiality is claimed by the Authority, when in all other cases, Authority discloses volume related information in their disclosure statement.
- v. In view of the observation made by the Authority in paragraph 18 of the disclosure statement that the scope of the present review will not be modified, we reiterate our request that the Authority should maintain product scope as determined in previous investigations.
- vi. Any modification / change in the scope of the investigation carried out in past without following complete process of law should not be clubbed in the present Product under Consideration.
- vii. The Authority in the recent investigation of Polyester Staple Fibre (PSF) from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand [F. No. 14/49/2016 DGAD dated 25.1.2018], decided not to impose anti-dumping duties despite having injury and dumping on the grounds that "The other producer in India, who has not joined the petition, holds the largest share of the demand and is playing a major role in the determination of prevailing prices of the subject goods as is clear from examination of the various submissions filed by the user industry." In that investigation, despite the fact that the other producer was treated as ineligible producer by the Authority in terms of Rule 2(b), his non-participation was considered to be fatal for the investigation.
- viii. There are three producers of the subject goods, the major producer M/s Century Rayon which accounts for almost 46% of total Indian production has not participated in the investigation. Further, M/s Century Rayon accounts for almost 35% of the demand in India. There is no explanation in the disclosure statement as to how the share of M/s Century Rayon is only 35% in demand when they account for 46% of the production. Therefore, the Authority is requested to kindly terminate the investigation as the major producer has not participated in the investigation.

- ix. It is submitted that the claim of the Domestic Industry regarding NIP computation is legally and factually incorrect. In this context, kind attention is invited to Section 2 (42C) of Income Tax Act 1961 which reads as under:

*(42C) "slump sale" means the transfer of one or more undertakings as a result of the sale for a lump sum consideration without values being assigned to the individual assets and liabilities in such sales.*

*Explanation 1 — For the purposes of this clause, "undertaking" shall have the meaning assigned to it in Explanation 1 to clause (19AA).*

*Explanation 2 — For the removal of doubts, it is hereby declared that the determination of the value of an asset or liability for the sole purpose of payment of stamp duty, registration fees or other similar taxes or fees shall not be regarded as assignment of values to individual assets or liabilities;*

- x. It may be seen that as per the above provision of the Income Tax Act, "slump sale" means the transfer of one or more undertakings. Thus, it is clear that under the 'slump sale route', the sale is of an undertaking or the business activity taken as a whole as a going concern and not of the individual assets. In this context, the Authority may refer to Annexure III of the Anti-Dumping Rules which envisages a reasonable return on the capital employed and not on the value of a business entity. In terms of the consistent practice of the Authority, the return is invariably allowed on the capital employed and not on the value of the business/concern. Therefore, any claim of Domestic Industry to obtain higher return on account of the slump sale value is completely misconceived and contrary to the express provisions of law. The reference to the valuation done by independent evaluator is also irrelevant as the return is to be allowed only on the basis of the actual depreciated value of the assets. In fact, it is clear that the claim of the Domestic Industry is without merit also on the ground that the proposition in effect would tantamount to revaluation of assets only. Such revaluation of assets is specifically disallowed in terms of Annexure III of the Rules.
- xi. The Authority has rightly observed that the sale from Kesoram Industries Limited to M/s Cygnet Industries Limited is in fact a transfer from the parent company to its fully owned subsidiary and, therefore, any such transaction is relevant from the point of view of the anti-dumping laws.
- xii. We humbly request the Authority to kindly confirm its stand of not allowing Domestic Industry any return on the value of the business as opposed to the return on the capital employed computed on the basis of the actual depreciated value of the fixed assets.
- xiii. It is clear from the disclosure statement that the applicant industry is not suffering any injury regarding any of the given parameter. On the contrary all these parameters are showing positive growth and stabilization of the applicant industry.
- xiv. The Authority has noted several instances in Annexure 4 of the disclosure statement of misrepresentation by the domestic industry in relation to the transfer of ownership of Kesoram Rayon to Cygnet industries at the time of filing of the petition. Respondents request the Authority to hold that initiation of investigation was bad in law due to such misrepresentation by domestic industry.
- xv. Determination of NIP by the Authority in accordance with Annexure III of the Anti-Dumping Rules and as noted in Annexure 4 of the disclosure statement is correct.
- xvi. There is improvement in all economic parameters of domestic industry during the injury investigation period. There is no price suppression/depression. Also, there is negative price underselling or undercutting during the period of investigation. Decline in production and sales in the POI is due to decline in demand and not due to imports.
- xvii. The Authority has also determined *de-minimis* margin of dumping for imports from subject countries. Authority has correctly rejected the possibility of diversion of exports of VFY to India from Pakistan and the claim regarding possibility of circumvention of goods.
- xviii. Thus, based on the analysis of dumping and injury to the domestic industry, it is clear that there is no present dumping or injury and there is no likelihood of dumping or injury in future.
- xix. Domestic industry has the burden to provide information regarding surplus capacities in China PR. The Authority should observe that domestic industry has failed to provide evidence regarding existence of surplus capacities.
- xx. There are stringent environmental norms and express prohibition in law in China PR on expansion of capacity for VFY. Regulation by the Ministry of Industry Information, Government of China in 2010 (and 2017) prohibits addition of new capacity of the subject product.



- xxi. Reports indicate that several VFY producers have shut down production of VFY in China PR which has resulted in reduction of overall capacity. Thus, there is no possibility of further addition of capacity or surplus capacity which may result in likelihood of dumping and injury.

#### **Examination by the Authority**

131. It is noted that the issues raised at post disclosure stage have already been examined by the Authority in above relevant paragraphs, however for the sake of the clarity of the submissions they are addressed as below:

- i. NIP and cost of production has been determined as per the provisions of the rules and the uniform practice followed in the Directorate for the calculations.
- ii. PCN wise analysis had been done for the data provided by the petitioner as well as the cooperating exporters. Conclusion on injury margin and dumping margin was drawn after due analysis of the PCN wise data and the same was used to arrive at the weighted average.
- iii. The normal value for the exporters has been constructed based on the cost of production of the most efficient domestic producer as per the uniform practice followed in the Directorate.
- iv. The imports from subject country are not being sold below the non- injurious prices of the domestic industry & the price undercutting from subject country is negative not only in POI but throughout the injury period.
- v. Share of imports from China in relation to total imports has further declined over the injury period; imports in relation to production and consumption have also decreased resulting in increase in domestic industry market share and net sales realization translating into mitigation of injury caused by the dumping from subject country.
- vi. M/s Kesoram Rayon was part of M/s Kesoram Industries Limited till 31.03.2016. M/s Cygnet Industries Limited had acquired the Rayon, Transparent paper and Chemical business undertaking of Kesoram Industries Limited at the close of business on 31st March 2016. Accordingly, a business transfer agreement was entered into between the Cygnet Industries Ltd and Kesoram Industries Limited to transfer the rayon, transparent paper and chemical business undertaking on a going concern basis through slump sale route at the total consideration of Rs 541 crore. The Business Transfer Agreement was amended on 27th May 2016, wherein the parties have agreed that the completion shall take place at the close of business as on 31st May 2016. Accordingly, KIL carried on the business operations of the undertaking during the two months period from 1st April 2016 to 31st May 2016 on behalf of purchaser M/s Cygnet Industries Limited. Cygnet Industries Limited the purchaser has subsequently become a 100% subsidiary of the seller Kesoram Industries Limited on 7th May 2016.
- vii. It was found during investigations that the value of Fixed Assets (tangible assets) as on 31.03.2016 was Rs 45.72 crore as per certified balance sheet of M/s Kesoram Rayon. However, the balance sheet of M/s Cygnet Industries Limited shows the value of Fixed assets as Rs 427.13 crore as on the same date.
- viii. The subsequent details indicate that the value was determined by an independent valuation agency. Since Cygnet Industries is 100% subsidiary of Kesoram Industries limited, revaluation of assets was not considered for return purpose, as it may amount to circumventing the Annexure-iii of the Customs Tariff (identification, assessment and collection of anti-dumping duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1955. Para 4 (viii) of Annexure-iii states that a reasonable return on average capital employed for the product may be allowed for recovery of interest, corporate tax and profit. Net Fixed Assets of both the petitioner companies has been adopted without considering any revaluation.
- ix. Annexure-iii to the Customs Tariff (identification, assessment and collection of anti-dumping duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1955 para (viii) inter alia states that the impact of revaluation of fixed assets shall not be considered in the calculation of capital employed.
- x. The Authority has also taken into account other relevant factors, since the Anti-dumping Duty is in force since 24th May 2006.
- xi. Authority has examined the contention of the Domestic Industry and other interested parties to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury with specific reference to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules. Clause (vii) of Annexure II to the rules read with Nirma Ltd. Vs Union of India 2017(346) E.L.T 328 (Guj) decided on 13/12/2016. It is reiterated that Authority has not equated “likely to occur injury” to “threat of injury”. The likelihood of injury has been based on the analysis of economic parameters throughout the injury period. This is the best available fact on record. Possibility of injury in future has not been established by Domestic Industry with any reliable evidence. The post – disclosure submission of DI on the same is based on assumptions and calculations that constraints the Authority to objectively examine likelihood of injury.
- xii. There is no consistency in the submissions made on likelihood by both domestic industry and cooperating exporters. Where interested parties, specially representatives from the Chinese government have claimed that manufacturing units in China are closing down due to environmental reasons with respect to the subject goods, at the same place, there are submissions from petitioner, quoting reports of Chinese government expanding

- capacities. Hence, it is difficult to conclusively determine likelihood of dumped imports and consequent injury to the domestic industry based on the argument of surplus capacities.
- xiii. The third country exports and stock inventories of exporters could not be ascertained, as no exporter responded and provided the requisite data. Domestic Industry has submitted the third country exports data and the same has been examined. The subject goods are exported to both India and Pakistan in different deniers. The demand of the specific deniers exported to Pakistan does not appear to coincide with the demand in India. Hence, the fear of diversion of exports to India is baseless.
- xiv. Analysis of various economic parameters shows overall economic health of the domestic industry has improved. The Authority notes that this improvement is mainly due to the anti-dumping measures in force. Thereby the Anti-dumping measures have served the intended purpose of mitigating the unfair advantage usurped/exercised by the exporters by dumping their goods.
- xv. The Authority also reiterates that India follows lesser duty rule while arriving at conclusion to impose anti-dumping remedial measures. As there is no injury to the domestic industry during the period of investigation, thereby, the antidumping trade remedial measures cannot be extended merely on the basis of dumping only.

### **CONCLUSIONS**

132. Having initiated and conducted the present review investigation into continued dumping, injury and causal link in terms of the Antidumping Rules, the Authority is of the view that the exports from the subject country are not causing material injury to the domestic industry. Further, the analysis of likelihood of injury in view of cessation of duties demonstrates that there is no reason for continuation of anti-dumping duties against the subject goods from the subject country. Having concluded as above, the Authority is of the view that continuation of anti-dumping duty, on the imports of the subject goods, originating in or exported from the China PR, is not required. Having observed that the existing antidumping duty is in existence since 24<sup>th</sup> May 2006, the Authority is of the opinion that existing anti-dumping duty has served the intended purpose.

133. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority